घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 154- सोमवार 06- अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका,चुनाव के बाद चुन-चुनकर हिसाब करेंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में चुनावी सभा में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार,घुसपैठ और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ने जनता को भय और असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया है। पीएम मोदी ने कहा...टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन-चुनकर हिसाब लिया जाएगा और जनता का लूटा हुआ पैसा वापस कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है और संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने संदेशखाली जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया। तृणमूल के शासन काल में बंगाल की डेमोक्रेसी में भयंकर बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को सीधा टीएमसी का समर्थन मिलता है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही है। दुनिया के बड़े-बड़े देश अपने देश घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे है। लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की बचाने की कोशिश होती है। इसलिए टीएमसी सरकार एसआईआर का विरोध करती है।

बंगाल में पीएम मोदी बोले...टीएमसी की सरकार बंगाल की पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही

यहां की निर्मम सरकार बंगाल की पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहुलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार आपने आगे किसी संवेधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने दो-तीन पहले ही देखा है,पूरे देश ने देखा है। देश के न्यायाधीशों को कैसे बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए,ये कैसी सरकार है। यै कैसी व्यवस्था है, जहां जज भी सुरक्षित नहीं है। ये निर्मम सरकार का महाजंगल राज है। ये टीएमसी न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम करती है।

पीएम मोदी बोले...एक ओर टीएमसी का करप्शन है,तो दूसरी भाजपा का भरोसा है...

टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। आज कूचबिहार में जो दिख रहा है वो आप सबका विश्वास है। इस बार बंगाल में एक और टीएमसी भय है,जिसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। एक ओर टीएमसी के करप्शन का भय है तो दूसरी तरफ विकास को रफ्तार देने वाली भाजपा का भरोसा है। एक और टीएमसी के घुसपैठ कराने का भय है तो एक ओर घुसपैठियों को भगाने वाली भाजपा पर भरोसा है। एक ओर संदेशखाली जैसी बहनों की चीखें और बेटियों पर होता अत्याचार है,दूसरी ओर नारी शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण की मोदी की गारंटी है। एक ओर बढ़ती बेरोजगारी और पलायन का भय तो दूसरी ओर आत्मनिर्भर बंगाल का भरोसा है।

बंगाल शक्ति पूजा की धरती है...

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। यहां आई सभी बहनों-बेटियो को बंगाल की हर बेटी से कहूंगा बीजेपी आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए मैदान में है। बीजेपी आएगी तो महिला सशक्तिकरण का द्वार खोलेगी। इसीलिए बहनों-बेटियों की पहली चॉइस बीजेपी है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 16-17-18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है।

असम के हिमंत बिस्वा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री सत्ता में आते ही जेल भेजेंगे : राहुल गांधी

असम,05 अप्रैल 2026। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी राज्य असम के बिश्वनाथ चारियाली में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा,'असम के हिमंत भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं,वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमंत को माफी मांगने पर भी नहीं बख्शा जाएगा। सत्ता में आते ही उन्हें जेल भेजेंगे। '

राहुल ने कहा...सत्ता में आते ही सरमा को जेल भेजेंगे

राहुल ने कहा, 'मुख्यमंत्री की बयानबाजी हताशा की प्रतीक है,क्योंकि उन्हें अपनी हार और भविष्य का डर है। हिरण को जिस तरह शेर से डर लगता है, उसी तरह हमारे 'बब्बर शेर' (गौरव गोगोई) से सरमा को डर लगता है और वह रात को सोते नहीं हैं। वह जानते हैं कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल भेजने वाले हैं। जब हमारी सरकार आएगी तब उन्हें असम की जनता और कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। '

असम की सरकार दिल्ली से चलती है : राहुल

राहुल ने कहा,'डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके मुख्यमंत्री को कंट्रोल कर रहे हैं। असम की सरकार मुख्यमंत्री नहीं,बल्कि दिल्ली से शाह चला रहे हैं। सरमा जानते हैं कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने 10 सालों में असम की संस्कृति और भाईचारे को चोट पहुंचाई है। अब जनता जाग चुकी है और वह इस नफरत के बाजार को बंद करने के लिए तैयार है।

गूगल ने लॉन्च किया Gemma 4
अब स्मार्टफोन भी बनेंगे सुपर स्मार्ट,बिना इंटरनेट चलेगा AI

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। टेक दिग्गज गूगल ने अपना नया ओपन-सोर्स एआई मॉडल Gemma 4 लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल डेटा सेंटर से लेकर स्मार्टफोन तक हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है।

कंपनी का दावा है कि Gemma 4 छोटे साइज में भी बेहद पावरफुल परफॉर्मेंस देता है और बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन काम कर सकता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और डीपमाइंड के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने इसे डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर बताया है। Gemma 4 को चार अलग-अलग साइज में पेश किया गया है। E2B और E4B छोटे मॉडल हैं, जो खासतौर पर स्मार्टफोन और ढ्ढश्वञ्ज डिवाइस के लिए डिजाइन किए गए हैं। 26B Mixture of Experts मॉडल मिड-लेवल परफॉर्मेंस देता है, जबकि 31B Dense मॉडल सबसे पावरफुल वर्जन है। गूगल के अनुसार, 31B मॉडल ने कई बड़े एआई मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है, जबकि इसका साइज उनसे काफी छोटा है। इससे डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सही मॉडल चुनने की आजादी मिलती है। Gemma 4 सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि एक एडवांस एआई प्लेटफॉर्म है। इसमें मल्टी-स्टेप रीजनिंग, मैथ्स और जटिल सवालों को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता है। साथ ही इसमें एजेंटिक वर्कफ्लो सपोर्ट है।

कांग्रेस का हिमंता की पत्नी पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति छिपाने का आरोप

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। असम विधानसभा चुनाव 2026 के बीच रविवार को दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके परिवार पर अब तक का सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया है। खेड़ा ने दावा किया कि भारत के संसदीय इतिहास में शायद ही किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ इतने गंभीर दस्तावेजी सबूत सामने आए हों। उन्होंने कहा कि हिमंता और उनकी पत्नी का नाम पहले भी जमीन हड़पने, मंदिर का चंदा चोरी करने और चिटफंड जैसे घोटालों में उछलता रहा है, लेकिन इस बार के खुलासे भारत की सीमाओं के पार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक या दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के अनुसार, उनके पास संयुक्त अरब अमीरात का 'गोल्डन कार्ड' है, जो मार्च 2022 में जारी हुआ था और 2027 तक वैध है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास एंटीगुआ और मिस्र के भी सक्रिय पासपोर्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि एक भारतीय नागरिक और सिटिंग मुख्यमंत्री की पत्नी को तीन-तीन देशों के पासपोर्ट की क्या आवश्यकता है? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह कोई अपराधी हैं या फिर चुनाव हारने के बाद देश छोड़कर फरार होने की तैयारी कर रही हैं? कांग्रेस के इन तीखे आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इन दावों को पूरी तरह से निराधार, मनगढ़ंत और 'राजनीतिक हताशा' का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में अपनी हार निश्चित देख अब उनके परिवार पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है।

गृह मंत्री शाह से जांच की मांग और नागरिकता पर सवाल

पवन खेड़ा ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ये दस्तावेज सही हैं, तो मुख्यमंत्री की पत्नी की भारतीय नागरिकता अवैध हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम में 'लुटेरों की सरकार' चल रही है और ये विदेशी पासपोर्ट इस बात का प्रमाण हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई को विदेश में सुरक्षित ठिकाना मिल चुका है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या सरकार इन पासपोर्टों की वास्तविकता की जांच कराएगी या अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए चुप रहेगी?

आचार संहिता लागू होने के बाद से पांच राज्यों में 651.51 करोड़ की नकदी जब्त : चुनाव आयोग

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026 । चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के मद्देनज़र लागू आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए अब तक 651.51 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और अवैध सामग्री जब्त की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। चुनाव आयोग के अनुसार, चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वॉड और 5,200 से ज्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जांच, तलाशी और नाकाबंदी अभियान चला रही हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश लगाया जा सके। आयोग की ओर से बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के माध्यम से 26 फरवरी से अब तक बड़ी मात्रा में अवैध वस्तुओं की जब्ती दर्ज की गई है। इसमें 53.2 करोड़ रुपये नकद, 79.3 करोड़ रुपये की शराब, 230 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 58 करोड़ रुपये की कीमती धातु और 231.01 करोड़ रुपये के अन्य मुफ्त उपहार शामिल हैं। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक जब्ती पश्चिम बंगाल में 319 करोड़ रुपये की हुई है। इसके बाद तमिलनाडु में 170 करोड़ रुपये, असम में 97 करोड़ रुपये, केरल में 58 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 करोड़ रुपये की जब्ती दर्ज की गई है।

बेटी के तलाक पर पिता ने ढोल-नगाड़े बजवाए,परिवार ने किया डांस,8 साल पहले मेजर से हुई थी शादी

मेरठ,05 अप्रैल 2026। जहां तलाक को आमतौर पर दुख, बदनामी और सामाजिक कलंक से जोड़ा जाता है, वहीं मेरठ में एक अनोखा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला। एक रिटायर्ड जज ने अपनी बेटी के तलाक को हार नहीं,बल्कि नई आजादी और खुशी का जश्न मनाया। ढोल-नगाड़ों की गूंज, फूलों के हार और परिवारजनों की खुशी के साथ बेटी का घर वापसी का स्वागत किया गया। रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी इकलौती बेटी प्रणिता शर्मा का स्वागत उसी सम्मान और गर्व के साथ किया, जिस तरह 2018 में उसकी विदाई की थी। परिवार के सदस्य काली टी-शर्ट पहने नजर आए, जिन पर लिखा था - 'I Love My Daughter '। मिठाइयां बांटी गई और पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया। मेरठ में शादी के 7 साल बाद प्रणिता शर्मा का मेजर गौरव अग्निहोत्री से तलाक हो गया। तलाक के बाद बेटी अपने घर आई तो ढोल-नगाड़े बजे। बेटी के साथ घरवाले नाचते हुए कोर्ट से घर तक आए। सबने एक जैसी टीशर्ट पहनी थी। जिस पर लिखा था- 'I Love My Daughter '. प्रणिता की शादी 14 दिसंबर 2018 को एक आर्मी मेजर से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही ससुराल में उनका व्यवहार कठोर था। समय के साथ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना बढ़ती गई।

अमित शाह ने पिनरई विजयन पर साधा निशाना
राज्य में सरकार बदलने का समय आ गया

केरल,05 अप्रैल 2026। केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कुन्नाथुनाडु निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं हैं, बल्कि राज्ये के भविष्य को सुधारने के लिए हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का वोट शेयर बढ़ा है। अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनाने का समय आ गया है। शाह ने ईस्टर के अवसर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ईसाई समुदाय से समर्थन की अपील की, ताकि केरल में सरकार बनाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भाजपा की नीति बहुत स्पष्ट है- सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टिकरण नहीं। हम इसी के तहत देशभर में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, जब केरल का एक संगठन पीएफआई यहां देश विरोधी गतिविधियां करता था, भाजपा सरकार ने एक ही दिन में देशभर में उसके सभी कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे डिब्बों का आधुनिकीकरण कर रहा है : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रेन के डिब्बों के आधुनिकीकरण के लिए बड़े प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रेल मंत्री ने बताया कि इस पहल के तहत नए डिब्बों के डिजाइन और बेहतर शौचालय मॉडल विकसित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा डिब्बों को नई सुविधाओं से लैस करके एक उन्नत नमूना डिब्बा पहले ही तैयार कर लिया गया है। वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने नए डिजाइन और बेहतर शौचालय सुविधाओं वाले डिब्बों के मॉडल तैयार किए हैं। एक मौजूदा कोच को अपग्रेड करके एक सैंपल कोच बनाया गया है। वैष्णव ने अपग्रेड किए गए कोच का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें बेहतर इंटीरियर और स्वच्छता सुविधाओं को दिखाया गया है, जिनका उद्देश्य यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाना है। यह कदम भारतीय रेलवे द्वारा अपने पूरे नेटवर्क में यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। रेल मंत्री की ये टिप्पणियां चल रहे बुनियादी ढांचे के उन्नयन कार्यों के साथ आई हैं, जिनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण भी शामिल है। वैष्णव के अनुसार, यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुनर्विकास योजना के तहत, निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्टेशन परिसर में लगभग 1,500 एआई-सक्षम कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे कर्मचारियों और विक्रेताओं को पहचान पत्र और वर्दी जारी की जाएगी ताकि उनकी बेहतर पहचान हो सके, साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए नए साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा, अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्टेशन को टैक्सी सेवाओं से जोड़ा जाएगा।

वैष्णव ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे सुरक्षा में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला है। लोकसभा में हाल ही में दिए गए एक लिखित उत्तर में, उन्होंने कहा कि गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, हाल के वर्षों में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मंत्री द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2025-26 में (28 फरवरी तक) मात्र 14 रह गई है।

किशोर की शोभायात्रा के दौरान हत्या,बोरे में मिली लाश

महाराष्ट्र,05 अप्रैल 2026। नागपुर में हनुमान जयंती की शोभायात्रा से लापता हुए 14 साल अर्थव ननोरे नामक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। उसकी अपहरण कर उसकी हत्या की गई है। अर्थव का शव बोरे में मिला, उसे हाथ-पांव बंधे हुए थे और गला घोंटकर पहले उसकी हत्या की गई फिर उसके शव को बोरे में बांधकर आरोपियों ने उसके हाथ-पाव बांध दिए थे। अथर्व यह नागपुर के गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन इलाके स्थित माहूरे पेट्रोल पंप के सामने स्थित हनुमान मंदिर में 2 अप्रैल को शाम 5 बजे वह शोभायात्रा में शामिल होने गया था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। शोभायात्रा से लापता होने और कहीं भी उसका सुराग न मिलने के कारण परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

अंजली दमानिया ने किया बड़ा दावा,कहा...एकनाथ शिंदे ने 17 बार अशोक खरात से फोन पर की बात! महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर विवाद गहरा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने दावा किया है कि अशोक खरात और कई बड़े नेताओं के बीच लगातार संपर्क थे। उनके आरोपों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। फोन कॉल,तस्वीरें और पुराने संबंध अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं।

एकनाथ शिंदे और अशोक खरात के बीच 17 बार बातचीत का दावा : अंजली दमानिया ने आरोप लगाया कि शिंदे सेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अशोक खरात के बीच अतीत में कम से कम 17 बार फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने यह दावा एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत में किया।

दमानिया के मुताबिक,उन्हें अशोक खरात के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये कॉल किस अवधि में हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सबसे लंबी बातचीत 21 मिनट तक चली थी।

शिंदे सेना का जवाब,फोन पर बात करना अपराध नहीं : दमानिया के आरोपों पर शिंदे सेना की ओर से राज्य के मंत्री उदय सामंत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को फोन करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। उनका कहना था कि केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर किसी की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। शिंदे खेमे ने साफ संकेत दिया कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है।

रूपाली चाकणकर और खरात के बीच 177 कॉल्स का दावा : अंजली दमानिया ने अपने आरोपों में एनसीपी (अजित पवार गुट) की नेता रूपाली चाकणकर का भी नाम लिया। उनके मुताबिक, अशोक खरात ने अपनी पत्नी के बाद सबसे ज्यादा बातचीत रूपाली चाकणकर से की थी। दमानिया का दावा है कि दोनों के बीच कुल 177 बार फोन पर बातचीत हुई, जिनकी कुल अवधि 33,727 सेकंड थी।

न्यायिक ढांचा मजबूत करना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है : सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के जोन-2 की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारें अब यह मानती हैं कि न्यायिक ढांचे को मजबूत करना कोई विकल्प नहीं,बल्कि बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तो संविधान सही मायने में जीवंत हो उठता है। सीजेआई सूर्यकांत ने देश भर में चल रहे विकास कार्यों पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,आंध्र प्रदेश,असम और अब तेलंगाना में अदालती परिसरों की नींव रखी है। इससे पता चलता है कि हर विचारधारा की सरकारें अदालतों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के महत्व को समझ रही हैं।

प्रस्तावित हाई कोर्ट परिसर के मॉडल और नक्शों को देखने के बाद सीजेई ने इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 100 एकड़ में फैला यह नया परिसर देश के सबसे बेहतरीन कोर्ट परिसरों में से एक होगा।

संपादकीय

बारूदी लपटों में झुलसती प्रकृति

कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने वाला चौथा सबसे बड़ा कारक युद्ध

मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है,जिसने अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने के हर संभव जतन किए हैं...यह आत्मघाती प्रवृत्ति मानवीय लालच और अंतहीन संचय की अंधी दौड़ का परिणाम है...

मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा जीव है,जिसने अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने के हर संभव जतन किए हैं। यह आत्मघाती प्रवृत्ति मानवीय लालच और अंतहीन संचय की अंधी दौड़ का परिणाम है। सब अपने नियंत्रण में लेने की चाहत ने न केवल पृथ्वी का तापमान बढ़ाया,बल्कि आपसी वैमनस्य और युद्धों ने इस विनाशकारी आग में घी डालने का काम किया है।

आज की झुलसाती गर्मी महज एक मौसम का बदलाव नहीं,बल्कि हमारे विनाशकारी कृत्यों की प्रतिध्वनि है। पिछले एक दशक से प्रकृति का बदलता व्यवहार हमारे सामने है। एक ओर जहां बढ़ती गर्मी अपना विकराल रूप दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक युद्धों ने पर्यावरण प्रदूषण का एक नया और घातक द्वार खोल दिया है।

बढ़ता तापीय संकट

विडंबना यह है कि जब पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए,तब युद्धों का दौर प्रकृति के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते;इनका प्रभाव सीमाओं को लांघकर हवा,मिट्टी और पानी को जहर बना देता है। युद्ध की विभीषिका केवल जान-माल तक सीमित नहीं रहती,बल्कि यह समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को भ्रमित और खंडित कर देती है। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा रणक्षेत्र बना हुआ है।

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव हो या इजरायल-गाजा और रूस-यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष-इन युद्धों ने मानवता के साथ-साथ प्रकृति को भी गहरे घाव दिए हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता;इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता है।

वर्तमान संघर्षों ने जहां ऊर्जा और तेल का संकट पैदा किया है,वहीं हथियारों से निकलने वाले जहरीले रसायनों ने जल और जमीन को मरणासन्न कर दिया है। टीएनटी और आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों में मौजूद लेड और यूरेनियम जैसे तत्व आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर देते हैं।

कुपित होंगे जब सागर

हमें यह भी सोचना होगा कि बढ़ते तापमान के बीच समुद्रों की क्या भूमिका होगी। जैसे-जैसे महासागर गर्म होंगे वातावरण में नमी बढ़ेगी। यह अतिरिक्त नमी भविष्य में कहां और किस रूप में आसमानी आफत या विनाशकारी वर्षा बनकर बरसेगी, इसकी कल्पना मात्र सिहरन पैदा करती है।

विकास की अंधी लालसा और अहंकार की तुष्टि के लिए लड़े जा रहे ये युद्ध अंततः मनुष्य को ही लील जाएंगे। जब मनुष्य केवल भोजन ही नहीं,बल्कि संसाधनों की छीना-झपटी के लिए एक-दूसरे के खून का प्यासा होगा,तब प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह तो बस अपने शांत स्वभाव को त्याग देगी और मनुष्य का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा!

विनाशकारी भविष्य की पदचाप

विशेषकर आधुनिक अग्निशस्त्रों और मिसाइलों से निकलने वाली अपार ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण में अवशोषित होकर तापक्रम को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। पिछले तीन-चार वर्षों के युद्धों ने जलवायु संकट को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी कठिन है।

फरवरी 2024 का महीना पिछले 175 वर्षों का सबसे गर्म फरवरी दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि हम क्लाइमेट इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं। यह तपिश केवल प्राकृतिक चक्र का हिस्सा नहीं,बल्कि मानव-निर्मित बारूदी धुएं की देन है। बदलते मौसम की ये चेतावनियां अब स्पष्ट और डरावनी हो चुकी हैं।

तेल की तलवार और कूटनीति की ढाल

पश्चिम एशिया संकट में भारत की अग्निपरीक्षा युद्ध की आग में तपती भारतीय अर्थव्यवस्था

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़,नई दिल्ली

दशकों पहले युद्ध केवल सीमाओं पर जमीन के टुकड़ों के लिए लड़े जाते थे लेकिन 2026 का यह दौर गवाह है कि आधुनिक युद्ध 'संप्रभुता' से ज्यादा 'संसाधनों' का है। युद्ध की गोलियां, मिसाइलें अब ऊर्जा की पाइपलाइनों और तेल के टैंकरों पर चलती है। पश्चिम एशिया में ईरान,इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ा यह त्रिकोणीय संघर्ष भी महज जमीन का विवाद नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा 'ऊर्जा आपूर्ति' पर नियंत्रण की जंग है। भारत के लिए यह संकट केवल पैट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है,जिसने देश के सामने एक अदृश्य 'ऊर्जा लॉकडाउन' का खतरा पैदा कर दिया है। जब संसद में प्रधानमंत्री ने इस संकट की तुलना 'कोरोना काल' की विभीषिका से की तो उनका आशय घर में बंद होने से नहीं बल्कि उस वैश्विक अनिश्चितता से था, जो किसी भी क्षण भारत की विकास दर के पहियों को जाम कर सकती है। यदि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर ताला लगता है तो भारत की रगों में दौड़ने वाला 60 प्रतिशत तेल और एलएनजी का प्रवाह थम जाएगा,जो देश को एक भयावह 'ऊर्जा लॉकडाउन' की ओर धकेल सकता है।

होर्मुज की घेराबंदी

विश्व मानचित्र पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह संकरा जलमार्ग है,जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी गुजरती है। ईरान द्वारा इस जलमार्ग को प्रभावित करने का अर्थ है,वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की गर्दन दबाना। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए इस युद्ध ने मात्र पांच हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों को 85 डॉलर से 110 डॉलर के पार पहुंचा दिया है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 40 प्रतिशत अकेले कतर से पूरा करता है। कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट पर हुए हमलों ने न केवल उत्पादन घटाया है बल्कि भारत के घरेलू चूल्हों तक पहुंचने वाली गैस की कीमतों में आग लगा दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर से उछलकर 110 डॉलर प्रति बैरल को छू रही हैं। भारत के लिए गणित सीधा और क्रूर है, कच्चे तेल में 10 डॉलर की हर बढ़ोत्तरी हमारे चालू खाता घाटे में लगभग 12-15 अरब डॉलर की वृद्धि करती है। यह स्थिति हमें दो टूक शब्दों में चेतावनी दे रही है कि पराई बैसाखियों पर टिकी ऊर्जा सुरक्षा कभी भी धराशायी हो सकती है।

सामरिक पैट्रोलियम भंडार: क्या पर्याप्त है चंद दिनों की सुरक्षा?

ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सीमित सामरिक पैट्रोलियम भंडार है। दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका,जापान और चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए 90 दिनों का'स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व' रखते हैं,वहीं भारत की स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में हमारे पास विशाखापट्टनम,मंगलुरु और पाडुर में कुल 53.3 लाख टन का भंडार है,जो मुश्किल से 9 दिन की आपूर्ति कर सकता है। हालांकि दूसरे चरण में चंडीखोल और बीकानेर जैसे स्थानों पर भंडार क्षमता बढ़ाकर इसे 60-65 दिनों तक ले जाने की योजना है लेकिन इसकी गति 'युद्धस्तर' पर नहीं है। हमारे मौजूदा भंडार का करीब 36 प्रतिशत हिस्सा खाली पड़ा है। एक तरफ हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ऊर्जा की 'लाइफलाइन' केवल कुछ दिनों के स्टॉक पर टिकी है। यदि आज हमारे पास 90 दिनों का सुरक्षित भंडार होता तो भारत को अपनी विदेश नीति में तटस्थता का नाटक नहीं करना पे ता बल्कि वह एक सशक्त वैश्विक खिलाड़ी की तरह अपना पक्ष रख सकता था। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य 30 दिनों के लिए बंद हो जाता है और भारत के लिए आपूर्ति बाधित होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 'वेंटिलेटर' पर आ जाएगी। इसलिए चंडीखोल और बीकानेर में प्रस्तावित दूसरे चरण के भंडारों का निर्माण युद्धस्तर पर होना अब विकल्प नहीं,अनिवार्यता है।

कूटनीतिक विवशता और स्वतंत्र विदेश नीति का संकट

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता आज तेल की निर्भरता के कारण परीक्षा की घड़ी में है। तेल की निर्भरता केवल आर्थिक बोझ नहीं बल्कि कूटनीतिक बेड़ियां भी है। भारत को अपने पुराने और रणनीतिक मित्र ईरान का साथ छोड़कर इजरायल और अमेरिकी समर्थित खाड़ी देशों के पाले में खड़े होने पर मजबूर होना पड़ा है। यह बदलाव केवल नीतिगत नहीं बल्कि विवशतापूर्ण है। खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और वहां से आने वाला 'रेमिटेंस' भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीय प्रवासियों के हितों और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ही भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता करना पड़ रहा है। जब तक हम ऊर्जा के लिए आयात पर 85 प्रतिशत निर्भर रहेंगे,तब तक हमारी विदेश नीति की चाबी विदेशी राजधानियों के हाथों में रहेगी और वाशिंगटन या तेहरान में होने वाली हर हलचल नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती रहेगी। यह युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची संप्रभुता केवल सीमाओं की रक्षा में नहीं बल्कि ऊर्जा की आत्मनिर्भरता में निहित है।

अफवाहों का बाजार और सरकारी डैमेज कंट्रोल

युद्ध के बीच भारत में लॉकडाउन की अफवाहों ने पैनिक पैदा किया है। हालांकि, तीन मंत्रियों निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि देश सुरक्षित है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत के पास तेल और गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विविधीकृत स्रोत हैं और पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन सतर्कता और ऊर्जा संरक्षण हमारा सामूहिक धर्म है। सरकार का यह स्पष्टीकरण अल्पकालिक राहत तो देता है लेकिन एक दीर्घकालिक प्रश्न भी छोड़ता है कि क्या हम हर संकट के समय केवल डैमेज कंट्रोल ही करते रहेंगे या भविष्य की नींव रखेंगे?

विकल्प नहीं,अनिवार्यता है वैकल्पिक ऊर्जा

वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ती आयात निर्भरता के इस दौर में वैकल्पिक ऊर्जा अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अनिवार्यता बन चुकी है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है और भारत को इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री की मुफ्त बिजली योजनाएं और रूफटॉप सोलर मिशन केवल नीतिगत पहल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सशक्त आधारस्तंभ हैं। भारत में 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं,जो बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर निर्भर हैं। यदि रसोई को इंडक्शन कुकिंग और एथनॉल आधारित विकल्पों की ओर मोड़ा जाए तो न केवल खर्च कम होगा बल्कि ऊर्जा आयात का बोझ भी घटेगा। लगभग 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली पर खाना बनाना एलपीजी की तुलना में किफायती है, वहीं कृषि अवशेषों से बनने वाला एथनॉल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। इससे 'अन्नदाता' ही 'ऊर्जादाता' बन सकता है। परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण भी उतना ही आवश्यक है। वर्तमान में तेल की सबसे अधिक खपत इसी क्षेत्र में होती है जबकि बिजली की हिस्सेदारी नगण्य है। यदि सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन को इलैक्ट्रिक किया जाए तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प भारत को स्थायी,स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में निर्णायक परिवर्तन करे।

बिजली खपत का बदलता स्वरूप

भारतीय अर्थव्यवस्था में बिजली का 42 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों में और 17 प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, कार्यालयों और दुकानों (वाणिज्यिक क्षेत्र) में बिजली की मांग बे ेगी। हमें कोयला आधारित बिजली (जो अभी भी हमारी रीढ़ है) से हटकर परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा की ओर तीव्र गति से मुड़ना होगा। सालाना 143 अरब डॉलर (2025 के आंकड़े) का तेल आयात एक ऐसा घाव है,जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। सूर्य और पवन के रूप में भारत के पास असीमित प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उन्हें 'ऊर्जा' में बदलने की इच्छाशक्ति और निवेश की गति अभी भी मंथर है।

भविष्य का रोडमैप : ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा

ईरान-इजरायल युद्ध ने भारत के लिए एक कठोर चेतावनी प्रस्तुत की है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित होता है तो यह केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 'आर्थिक प्रलय' का कारण बन सकता है। उर्वरक,ईंधन, सेमीकंडक्टर, हर आपूर्ति शृंखला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत को त्वरित,ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, रणनीतिक भंडार का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है। अगले 24 महीनों में कम से कम 90 दिनों का तेल और गैस रिजर्व तैयार करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि किसी भी वैश्विक व्यवधान के समय देश की ऊर्जा आवश्यकताएं प्रभावित न हों। दूसरा, ऊर्जा विविधीकरण पर आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। रूस,मध्य एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के साथ दीर्घ कालिक आपूर्ति समझौते, पाइपलाइन परियोजनाएं और वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करना समय की मांग है। तीसरा,परमाणु ऊर्जा, सौर शक्ति और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। ये केवल स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत नहीं बल्कि स्थायी ऊर्जा सुरक्षा के स्तंभ हैं। अंततः, यह स्पष्ट है कि वैश्विक शांति हमारे नियंत्रण में नहीं परंतु अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। आत्मनिर्भरता अब केवल नारा नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त बन चुकी है। यदि हम आज निर्णायक कदम नहीं उठाते तो भविष्य का अंधकार हमारी ही निष्क्रियता का परिणाम होगा।

जेनेरिक से नवाचार तक का सफर

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार हरियाणा

सस्ती दवाओं के निर्यात में अग्रणी,पर सक्रिय संघटकों के लिए आयात पर निर्भरता

भारत आज वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन चुका है। विश्व की फार्मेसी के रूप में उसकी पहचान केवल एक उपमा नहीं,बल्कि उसकी उत्पादन क्षमता,निर्यात विस्तार और वैश्विक जनस्वास्थ्य में उसके योगदान का सशक्त प्रमाण है। वर्ष 2025-26 तक भारतीय औषधि बाजार 50 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है और वैश्विक जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में उसका योगदान 20 प्रतिशत से अधिक है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी भारतीय कंपनियां लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करती हैं, जबकि अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता में भारत की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। यह उपलब्धि 1970 के दशक में पेटेंट कानूनों में हुए परिवर्तन का परिणाम है, जब भारत ने प्रक्रिया पेटेंट प्रणाली को अपनाकर घरेलू उद्योग को सशक्त किया और सस्ती दवाओं के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया।

किन्तु इस चमकदार उपलब्धि के पीछे एक गहरा विरोधाभास भी छिपा हुआ है। भारत जहां एक ओर तैयार दवाओं का प्रमुख निर्यातक है, वहीं दूसरी ओर उनके निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल और सक्रिय औषधीय संघटकों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। अनुमानतः भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 60 से 70 प्रतिशत सक्रिय औषधीय संघटक विदेशों से आयात करता है, जिसमें प्रमुख हिस्सा चीन से आता है। पेनिसिलिन जी,क्लैवुलैनिक अम्ल और पैरासिटामोल जैसे महत्वपूर्ण संघटकों के मामले में यह निर्भरता 80 प्रतिशत से भी अधिक है। यह स्थिति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

कोविड-19 महामारी ने इस निर्भरता की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। चीन में लॉकडाउन के कारण आपूर्ति बाधित होते ही भारत में दवा उत्पादन प्रभावित हुआ। अनेक औषधि निर्माण इकाइयों को उत्पादन घटाना पड़ा और कुछ को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान भारत की औषधि उत्पादन क्षमता को तुरंत प्रभावित कर सकता है। इस अनुभव ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बना दिया।

इसी संदर्भ में सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लगभग 16,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की,जिसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर सक्रिय औषधीय संघटकों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है,फिर भी अनेक संरचनात्मक समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। उच्च उत्पादन लागत,तकनीकी सीमाएं तथा कठोर पर्यावरणीय नियमों के कारण कई उत्पादन इकाइयां बंद हो चुकी हैं,जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित हो गई है। नियामक ढांचे की कमजोरी भी इस क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर औषधि नियंत्रण संस्थाओं में संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गुणवत्ता नियंत्रण में खामियों के कारण कई भारतीय औषधि निर्माण इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ मामलों में विदेशी नियामक संस्थाओं द्वारा आयात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनका कारण निर्माण प्रक्रियाओं में त्रुटियां और गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन रहा है। इससे भारत की वैश्विक साख प्रभावित होती है और निर्यात संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसके अतिरिक्त,नकली दवाओं का बढ़ता बाजार भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। यह न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा है,बल्कि औषधि उद्योग की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है। मूल्य नियंत्रण नीतियों के कारण कंपनियों की लाभप्रदता सीमित होती है, जिससे वे अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं कर पातीं और मुख्यतः जेनेरिक उत्पादन तक ही सीमित रह जाती हैं। अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी भारतीय औषधि क्षेत्र की एक बड़ी कमजोरी है। जहां वैश्विक औषधि कंपनियां अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा अनुसंधान पर खर्च करती हैं, वहीं भारत में यह अनुपात अपेक्षाकृत कम है। इसका परिणाम यह है कि भारत नवाचार आधारित दवाओं,जैविक औषधियों और व्यक्तिगत चिकित्सा जैसे उभरते क्षेत्रों में पीछे रह जाता है। भविष्य में इन क्षेत्रों का महत्व तेजी से बढ़ने वाला है,और यदि भारत ने समय रहते इस दिशा में निवेश नहीं बढ़ाया,तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है।

कौशल विकास की कमी भी एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में सामने आती है। आधुनिक औषधि निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है,जो वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। शिक्षा संस्थानों और उद्योग के बीच समुचित समन्वय के अभाव में छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे नवाचार की गति प्रभावित होती है। पर्यावरणीय चुनौतियां भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। औषधि निर्माण प्रक्रिया ऊर्जा-गहन और प्रदूषणकारी होती है, जिसके कारण पर्यावरणीय मानकों का पालन करना महंगा पड़ता है।

इससे उत्पादन लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है। साथ ही, डिजिटल प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

मन करता है भोले

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
गांधीनगर,इन्दौर

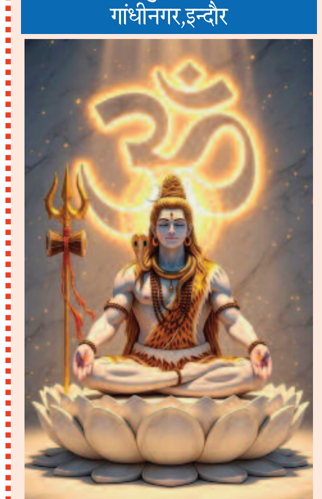

मन करता है मन-मन भोले,
गीत तेरे ही गाता जाऊं,
नहीं किसी भी अर्थ तत्व में,
अपना जीवन ललचाऊं।
मन करता है ....
स्वांसों की गठरी भर कर जो,
भोले नें हमको दी है,
यूं ही व्यर्थ गवाएं ना हम,
जिसकी सीमा निश्चित की है।
मन करता है ...
कहीं किसी की भक्ति में रोड़ा,
ना बन जाएं भोले हम,
जैसा-भी हो थोड़ा-थोड़ा,
साथ भक्ति में गाएं हम।
मन करता है....
होंठ हमारे जब-भी खोलें,
बस उनसे भोले ही बोलें,
सब्र का बांध न टूटने पाए,
बस जीवन मुस्काता जाए।
मन करता है ....
भोले जड़-चेतन के स्वामी,
संग चलने की भर ली हामी,
बिन भोले के हम हैं खाली,
संग भोले मन खिली है डाली।
मन करता है ....

कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से तीन प्रश्न कीजिए मैं यह क्यों कर रहा हूं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े – चाणक्य

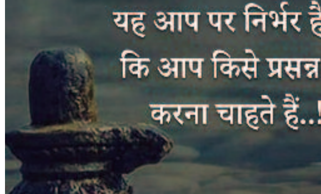

नौकरीपेशा महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों के साथ जीवन की दौड़

डॉ. विजय गर्ग
मलोट पंजाब

आज के आधुनिक समाज में नौकरीपेशा महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। वे न केवल घर का रखरखाव करती हैं,बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवार बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन इस योगदान के साथ उन्हें दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना पड़ता है। एक तरफ कार्यालय की ड्यूटी और दूसरी तरफ घर की देखभाल।

नौकरीपेशा महिला की सुबह ज्यादातर दूसरों से पहले शुरू होती है। घर के सभी काम,बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और फिर समय पर कार्यालय पहुंचना यह सब एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। ऑफिस में भी उन्हें अपना काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना पड़ता है। दिन भर की थकान के बाद भी वे घर आकर दोबारा घरेलू कार्यों में शामिल हो जाती हैं। यह दोहरी जिम्मेदारी कभी-कभी महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव का कारण बनती है। समय की कमी,अपने लिए समय न मिलना और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देता है। फिर भी, वे हर कठिनाई का सामना अपनी हिम्मत और समर्पण से करते हैं। समाज में अभी भी यह धारणा पूरी तरह से नहीं बदली है कि घरेलू काम केवल महिला

की जिम्मेदारी है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हैं, तो नौकरीपेशा महिलाओं का जीवन काफी आसान हो सकता है। साथ ही, कार्यस्थल पर भी उनके लिए सुविधाएं और लचीले समय की व्यवस्था होनी चाहिए। आज के समय में महिला सिर्फ घर की देखभाल तक ही सीमित नहीं रही। वह आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। चाहे वह विज्ञान, शिक्षा,बैंकिंग या राजनीति का क्षेत्र हो। लेकिन जब एक महिला घर से बाहर काम करने जाती है, तो उसकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय दोगुनी हो जाती हैं।

घर और कार्यालय के बीच संतुलन : एक नौकरीपेशा महिला के लिए दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है। रसोई का काम,बच्चों को तैयार करने और बुजुर्गों की देखभाल करने के बाद वह अपने कार्यालय के लिए रवाना होती है। कार्यालय में वह अपनी पूरी मेहनत और योग्यता के साथ काम करती है,लेकिन शाम को घर लौटने पर ही वह फिर से गृहिणी की भूमिका में आ जाती है। मानसिक और शारीरिक बोझ दोहरी भूमिका निभाते हुए महिलाएं अक्सर सुपरवुमन बनने की कोशिश करती हैं। इस दौड़ में वे अपने स्वास्थ्य और आराम को पीछे छोड़ देती हैं। थकान पूरे दिन काम करने के बाद भी रात में घर के कामों की चिंता करना मानसिक थकान का कारण बनता है। **अपराध बोध:**कभी-कभी काम की व्यस्तता के कारण वे बच्चों को पूरा समय नहीं दे पाते,जिससे उन्हें अंदर से दोषी महसूस होने लगता है। सामाजिक चुनौतियां हमारा समाज अभी भी पूरी तरह से मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। आज भी यह अपेक्षा की जाती है कि चाहे महिला कितनी भी बड़ी अधिकारी क्यों न हो, घर का सारा काम उसकी जिम्मेदारी होती है। कार्यस्थल पर भी कभी-कभी महिलाओं को पूर्वाग्रह या कम समझा जाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि नौकरीपेशा महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं। वे अपने घर और काम दोनों को अच्छी तरह से संभालती हैं। उनकी कुशलता,उत्साह और समर्पण हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई को इरादे के बल से जीया जा सकता है। समाज का कर्तव्य है कि वह उनका सम्मान करे और उन्हें समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करे।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 महिलाओं को कुचला,मौके पर ही मौत...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर शहर से लगे ग्राम भिट्ठीकला के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल जा रही तीन महिलाओं को कुचल दिया,जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सामने से आ रहे ट्रेलर से जा भिड़ी और उसके परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार,तीनों महिलाएं रविवार शाम करीब 6:45 बजे सब्जी खरीदकर घर लौट रही थीं। तभी अंबिकापुर की ओर से तेज गति में आ रही स्कॉर्पियो (क्रमांक सीजी 15 ईएच-8874) ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ गईं। हादसे के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गया। इस घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए और आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर वाहन से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी,जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थिति को देखते हुए लोगों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया,जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत कर यातायात बहाल करने की कोशिश की। बाद में मृत महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मृतकों की पहचान ग्राम जोगीबांध निवासी मुन्नी बाई (50 वर्ष), श्यामपति राजवाड़े (55 वर्ष) और रामबाई (50 वर्ष) के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्कॉर्पियो चालक की पहचान व दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा।

अंबिकापुर हत्याकांड का खौफनाक सच

क्रूरता की हदें पार...जांच में जुटी पुलिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

शांत माने जाने वाले अंबिकापुर शहर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है,जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक अज्ञात महिला की निर्मम हत्या के मामले में अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं,वे इस घटना को और भी भयावह बना रहे हैं।

घटना कैसे सामने आई

जानकारी के अनुसार,शहर के एक सुनसान इलाके में स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ एक महिला का शव देखा,जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी,जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो गया कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है।

शव की हालत ने बढ़ाई दहशत

मृतका के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक,शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव थे और अत्यधिक हिंसा के संकेत मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पसलियों सहित अंदरूनी अंगों को गंभीर क्षति पहुंची,हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। इतना ही नहीं,आरोपियों ने महिला की पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया,जिससे उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया।

दुष्कर्म की आशंका

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इस मामले को कई एंगल से जांच रही है। शुरुआती जांच में दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है,लेकिन इस संबंध में अंतिम पुष्टि मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही होगी।

सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध

जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध व्यक्ति को घटना के बाद रेलवे स्टेशन क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है। यह फुटेज अब जांच का अहम हिस्सा बन चुका है और पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है।

पहचान और रिश्तों की जांच

पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं मृतका और आरोपी के बीच पहले से कोई जान-पहचान या संबंध तो नहीं था। कुछ सूत्रों के अनुसार,यह मामला व्यक्तिगत विवाद या संबंधों से जुड़ा हो सकता है,लेकिन इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस,फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का दावा किया है।

शहर में दहशत,लोगों में आक्रोश

इस निर्मम हत्याकांड के बाद शहर में भय और आक्रोश का माहौल है। लोग इस घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

बांसवाड़ी क्षेत्र में कथित अवैध कटाई पर आप नेता ने उठाए सवाल,जांच की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

आम आदमी पार्टी के नेता राजेन्द्र बहादुर सिंह ने अंबिकापुर के बांसवाड़ी क्षेत्र में कथित अवैध लकड़ी कटाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि रविवार सुबह के वीडियो एवं फोटो में बड़ी संख्या में लोग जंगल में घूम-घूम कर लकड़ी काटते दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार,करीब 50 से 60 लोग इस गतिविधि में शामिल नजर आ रहे हैं,जिससे क्षेत्र के छोटे जंगल पर खतरा उत्पन्न हो गया है। राजेन्द्र बहादुर सिंह ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौके पर न तो बीट गार्ड की उपस्थिति दिख रही है और न ही प्रभावी निगरानी के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन उपज नाके भी बंद पड़े हुए हैं, जिससे अवैध कटाई को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने हाल ही में वन्यजीवों, विशेषकर हिरण की मौत के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा वीडियो जारी कर वन विभाग का बचाव किया गया था,लेकिन वर्तमान स्थिति कई सवाल खड़े करती है। उनका कहना है कि यदि इस प्रकार खुलेआम कटाई हो रही है, तो संबंधित विभाग की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। आप नेता ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही सरगुजा जिले के संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने जंगलों की सुरक्षा के लिए ठोस और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त,उन्होंने संबंधित बीट गार्ड एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, यहां तक कि सेवा से बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

बलरामपुर में इंसानियत का 'काला चेहरा'! झाड़ियों में लावारिस मिली नवजात,शरीर पर रेंगती चीटियों ने झकझोर दिया कलेजा

-संवाददाता-
बलरामपुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। कोटराही और वाड्रफनगर के बीच जंगल किनारे झाड़ियों में एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में मिली। जानकारी के अनुसार, महुआ चुनने जंगल गई महिलाओं को अचानक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक नवजात बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई है। बच्ची के शरीर पर चीटियां लगी हुई थीं, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। महिलाओं ने तत्काल इसकी सूचना चाइल्डलाइन को दी। सूचना मिलते ही चाइल्डलाइन की टीम ने स्थानीय पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर तत्काल रेस्क्यू किया। बच्ची को पुलिस की मदद से पहले प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। घटना वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नवजात को इस हालत में छोड़ने वाले अज्ञात व्यक्तियों की तलाश की जा रही है.यह घटना एक बार फिर समाज के उस काले चेहरे को उजागर करती है, जहां मासूमों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं.मामले में वाड्राफनगर पुलिस ने चाइल्ड लाइन को भी इसकी सूचना दी है।

जहां से शांति का संदेश निकला आज वही जगह अशांत : बिशप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

पास्का जागरण अंधकार पर प्रकाश का,मृत्यु पर जीवन का शैतान पर ईश्वर की विजय का सबसे बड़ा उत्सव है। सदियों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। दुनिया के लिए जहां से शांति का संदेश निकला आज वही जगह अशांत है इजराइल के येरूसलम में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है राजनीतिक अस्थिरता से विश्वासियों में भय का वातावरण बना हुआ है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इस वर्ष जैतून पहाड़ से येरूसलम शहर में खजूर की डालियां हांथ में लेकर निकलने वाला परम्परागत जुलूस भी नहीं निकल सका। उक्त बातें सरगुजा धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप अंतोनिस बड़ा ने प्रभु ईशा के मृत्यु पर विजय के पर्व ईस्टर की पूर्व संध्या पर नवापारा स्थित बेदाग इश्माता महा गिरिजाघर में समुदाय को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कही। चर्च परिसर में शनिवार रात 10 बजे से विशेष प्रार्थना प्रारम्भ हुई और देर रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। पूण्य शनिवार की रात 10 बजे पास्का मोमबत्ती के आशीष के बाद समुदाय द्वारा घरों लाई हुई मोमबत्तियां पास्का मोमबत्ती से प्रज्ज्वलित कर समस्त धर्म विधियां प्रारंभ हुई।

दिल्ली जैसी निर्भया कांड पर भाजपा के महिला शक्ति की चुप्पी बेहद गंभीर : लिली श्रीवास

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

शहर के सद्भावना चौक पर महिला से दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्याकांड को लेकर युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास के नेतृत्व में सोमवार को युवा कांग्रेस सरगुजा ने गांधी चौक स्थित डेटा सेंटर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के साथ-साथ,जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव लिली श्रीवास ने कहा कि दिल्ली जैसी निर्भया कांड पर भाजपा के महिला शक्ति की चुप्पी बेहद गंभीर है। वास्तव में महिलाओं के प्रति होने वाले घृणित अपराधों से भाजपा को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि ऐसे अपराधियों का यह दल फूलमालाओं से स्वागत करती। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कल महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। यह बतलाता है कि इस घटना को लेकर महिलाओं में कितना आक्रोश है। निगम में नेता प्रतिपक्ष शफ़ी अहमद ने कानून व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक महिला जिसके साथ बीच चौराहे पर हैवानियत हो रही थी वो सहायता के लिए रात 1 बजे से 4 बजे

तक चीखती रही लेकिन शहर की सुस्त पुलिस पेट्रोलिंग को कुछ अता पता ही नहीं चला। निगम प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन के नाम पर अम्बिकापुर निगम में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा रोड लाईट तक का सही इंतजाम नहीं कर पा रही है। सडक़ों पर पसरे अंधेरे ने इन वारदातों की संभावनों को और भ बढ़ा दिया है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव ने कहा है कि आरोपी के गिरफ्तार होने तक युवा कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल,संजय विश्वकर्मा,मों इस्लाम, इंद्रजीत सिंह धंजल,सीमा सोनी,लक्ष्मी दास,दुर्गेश गुप्ता,मदन जायसवाल,लोकेश कुमार,आलोक सिंह, अशफाक अली,विकल झा,प्रीति सिंह,सोहन जायसवाल,रजनीश सिंह,निकी खान,सतीश बारी, अविनाश कुमार,अमित सिंह,विकास गुप्ता,आतिफ खान,आकाश अग्रहरि शामिल रहे।

ओवरटेक विवाद में फार्महाउस पर हमला,कार में तोडफ़ोड़,5 आरोपी गिरफ्तार

ऑटो चालक ने साथियों संग घुसकर की मारपीट,डंडों-पत्थरों से वाहन क्षतिग्रस्त

-संवाददाता-
धौरपुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ककनी में ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और तोडफ़ोड़ तक पहुंच गया। ऑटो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार सवार के फार्महाउस में घुसकर हमला किया और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार,प्रार्थी रोहितेश्वर प्रताप सिंह ने 4 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 2 अप्रैल को वह

धौरपुर से ककनी स्थित अपने फार्महाउस जा रहा था। चिलम नाला के पास उसने एक ऑटो को ओवरटेक किया, जिसके बाद ऑटो चालक कादिर खान फार्महाउस पहुंचकर गाली-गलौज कर चला गया। इसके बाद जब प्रार्थी डुमरडीह हाई स्कूल के पास पहुंचा,तो कादिर खान ने उसे रोककर विवाद किया। इसी दौरान अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देख प्रार्थी कार मोडक़र निकलने लगा, तभी उसकी कार ऑटो से टकरा गई। कुछ देर बाद आरोपी कादिर खान अपने साथियों मोहम्मद खान, हयात खान, अल्ताफ खान, फरहान खान व अन्य के साथ फार्महाउस पहुंचे और प्रार्थी के साथ मारपीट की। कर्मचारियों के बीच-बचाव करने पर आरोपी भाग निकले,लेकिन जाते-जाते कार को डंडों और पत्थरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

आरोपियों पर कई धाराओं में केस : पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ धारा 126(2), 191(1), 333, 296, 351(3), 115(2), 324(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे जांच जारी है।

पहले भी हुआ था विवाद : पुलिस के अनुसार, ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में बढ़ता गया और दोबारा आमना-सामना होने पर घटना ने हिंसक रूप ले लिया। हमले के दौरान फार्महाउस के कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला जिससे बड़ा हादसा टल गया।

एमसीबी में 'सुशासन' या मनमानी? उच्च वर्ग शिक्षक बना शिक्षा विभाग का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी,प्राचार्य-व्याख्याताओं में भारी आक्रोश

नियम-कायदों को दरकिनार कर कनिष्ठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी...वरिष्ठ शिक्षकों को देना पड़ रहा आदेश पालन...'हॉटलाइन' से नियुक्ति के आरोप

नियम ताक पर,कनिष्ठ को कमानः एमसीबी में शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

- वरिष्ठ दरकिनार,कनिष्ठ को अधिकारः एमसीबी शिक्षा विभाग में मचा बवाल
- 'हॉटलाइन' से पद या नियमों का खेल ? एमसीबी में शिक्षक बना बड़ा अधिकारी
- जहां व्याख्याता पीछे और शिक्षक आगेः एमसीबी शिक्षा विभाग में अनोखी व्यवस्था
- एमसीबी में अजीब सुशासनः उच्च वर्ग शिक्षक देगा प्राचार्य को आदेश!
- पद छोटा, जिम्मेदारी बड़ीः एमसीबी में शिक्षा व्यवस्था बनी सवालों के घेरे में

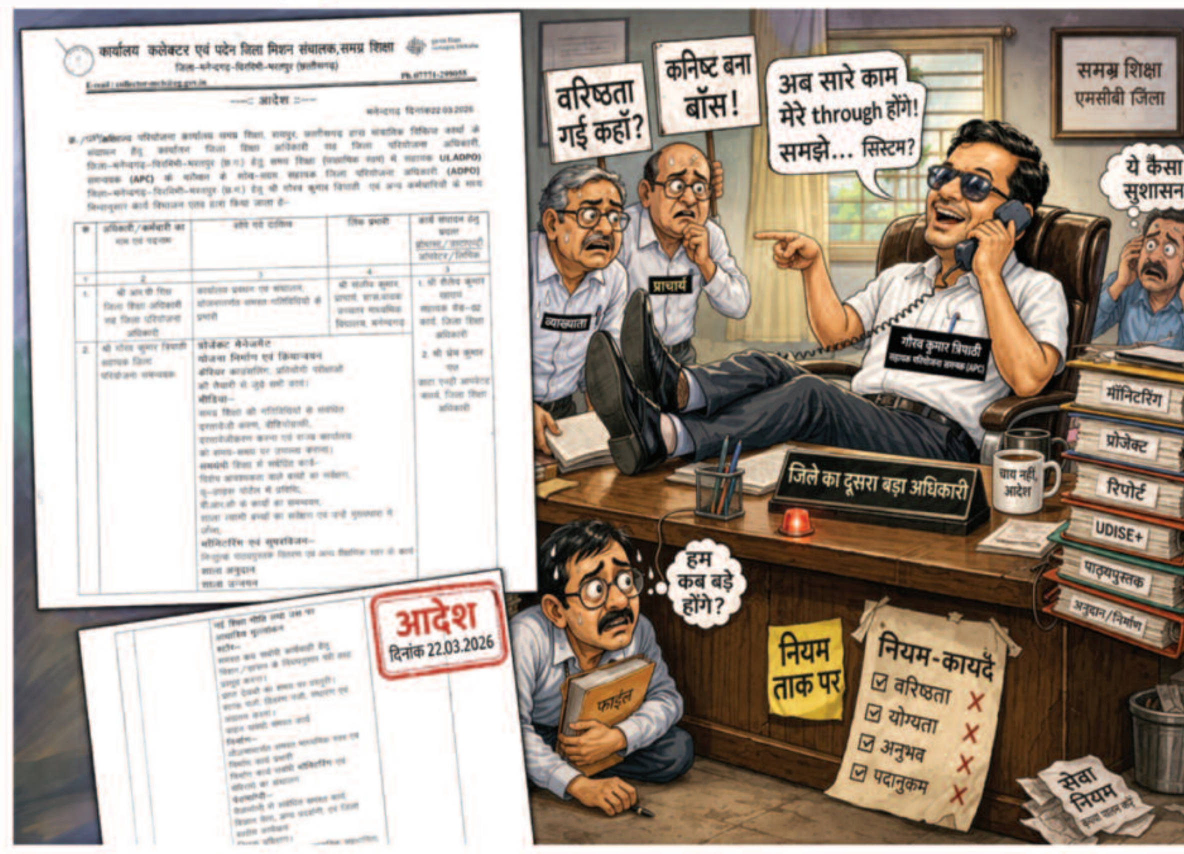

विशेष रिपोर्ट

एमसीबी,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। एमसीबी जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है,जिसने प्रशासनिक व्यवस्था, नियमों की पारदर्शिता और 'सुशासन' के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, आरोप है कि जिले में नियम-कायदों को दरकिनार करते हुए एक उच्च वर्ग शिक्षक को शिक्षा विभाग का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया गया है, जबकि यह पद सामान्यतः व्याख्याता या प्राचार्य कैडर के लिए निर्धारित माना जाता है,इस निर्णय के बाद जिले के प्राचार्यों और व्याख्याताओं में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है, शिक्षकों का कहना है कि अब उन्हें अपने से कनिष्ठ श्रेणी के शिक्षक के आदेशों का पालन करना पड़ रहा है, जो न केवल सेवा नियमों के खिलाफ है बल्कि उनके आत्मसम्मान और कार्यप्रणाली पर भी असर डाल रहा है।

एमसीबी जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा 22 मार्च 2026 को जारी एक आदेश अब बड़े प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गया है, कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,समग्र शिक्षा कार्यालय से जारी इस आदेश में कार्य विभाजन इस प्रकार किया गया है, जिससे जिले के प्राचार्यों और व्याख्याताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, आदेश के अनुसार गौरव कुमार त्रिपाठी (सहायक परियोजना समन्वयक - एपीसी) को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जो सामान्यतः वरिष्ठ कैडर–प्राचार्य या व्याख्याता– के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इस आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी की निगरानी में कार्य करते हुए गौरव कुमार त्रिपाठी को परियोजना संचालन, मॉनिटरिंग,शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन, दस्तावेजीकरण और विभिन्न योजनाओं के संचालन जैसे अहम कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जितेंद्र कुमार (प्राचार्य) और अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी निर्धारित की गई है, लेकिन कार्यों की प्रकृति और नियंत्रण की स्थिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, शिक्षकों का कहना है कि इस आदेश के बाद स्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें अपने से कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी से निर्देश लेना पड़ रहा है, जो सेवा नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत है, आदेश में जिम्मेदारियों का जो विभाजन किया गया है,उससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पदानुक्रम की अनदेखी कर एक विशेष व्यक्ति को प्रभावी भूमिका में स्थापित किया गया है, अब यह मामला केवल एक आदेश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा विभाग की पारदर्शिता,नियमों के पालन और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

क्यों भड़का आक्रोश? 'कनिष्ठ देगा आदेश'

जिले के प्राचार्य और व्याख्याताओं का कहना है कि इस आदेश के बाद उन्हें अपने से कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारी से निर्देश लेना पड़ रहा है, एक व्याख्याता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा यह सेवा नियमों के खिलाफ है, जिस पद के लिए वर्षों का अनुभव और वरिष्ठता चाहिए, वहां एक उच्च वर्ग शिक्षक को बैठा दिया गया है, शिक्षकों का यह भी कहना है कि इससे न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, बल्कि कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है।

कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम? 'धीरे-धीरे बना प्रभाव'

सूत्रों के अनुसार, यह नियुक्ति अचानक नहीं हुई, बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षक पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छोटे कार्यों में सहयोग के नाम पर नियमित रूप से उपस्थित रहने लगे, धीरे-धीरे उनकी सक्रियता बढ़ी और फिर उन्हें जिले के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित कर दिया गया, यह पूरा घटनाक्रम कई शिक्षकों को 'पूर्व नियोजित रणनीति' का हिस्सा प्रतीत हो रहा है।

'हॉटलाइन कॉल' और राजनीतिक दबाव के आरोप-

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह सामने आया है कि इस नियुक्ति के पीछे राजधानी से आए एक 'हॉटलाइन कॉल' का प्रभाव रहा है, आक्रोशित व्याख्याताओं का दावा है कि संबंधित शिक्षक को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते नियमों को शिथिल कर यह आदेश जारी किया गया, हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि इसमें सच्चाई है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिह्न है।

कलेक्टर की भूमिका पर भी उठे सवाल

जिला कलेक्टर,जिन्हें आमतौर पर सख्त और नियमों का पालन करने वाला अधिकारी माना जाता है, इस आदेश के बाद सवालों के घेरे में हैं,शिक्षकों का कहना है कि या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई,या फिर किसी दबाव में यह निर्णय लिया गया,अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है।

अन्य पदों पर भी 'कब्जे' के आरोप

शिक्षकों का आरोप है कि यह कोई एकल मामला नहीं है,जिले में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी उच्च वर्ग शिक्षकों को बैठाया गया है,जिससे पूरी व्यवस्था असंतुलित हो गई है, स्थिति यह बन गई है कि प्राचार्य, व्याख्याता,वरिष्ठ शिक्षक सभी को कनिष्ठ श्रेणी के कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है।

युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों में भी असंतोष

इस विवाद का असर उन शिक्षकों पर भी पड़ा है, जिन्हें युक्तियुक्तकरण के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा गया है,उनका कहना है कि यदि 'जुगाड़ और पहुंच' के आधार पर पद और पोस्टिंग मिल रही है, तो उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए,अब उनके बीच यह मांग उठ रही है कि उन्हें भी घर के आसपास पदस्थ किया जाए या फिर पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए।

सबसे बड़ा सवालः नियम या प्रभाव?

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या प्रशासनिक नियम अब केवल कागज़ों तक सीमित रह गए हैं? यदि वरिष्ठता और योग्यता को दरकिनार कर नियुक्तियां होंगी, तो शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित होगी,अधिकारियों का मनोबल गिरेगा और सिस्टम में अव्यवस्था बढ़ेगी

व्यवस्था की साख दांव पर

एमसीबी जिले का यह मामला अब केवल एक आदेश का विवाद नहीं रह गया है,बल्कि यह शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता की परीक्षा बन चुका है, अब देखना यह होगा कि, क्या इस आदेश की समीक्षा होगी? क्या नियमों के अनुसार सुधार किया जाएगा? या फिर एक व्यक्ति के लिए अलग व्यवस्था जारी रहेगी?

अंतिम कटाक्ष

जहां वरिष्ठ खड़े हैं लाइन में... और कनिष्ठ बैठा है कुर्सी पर... वहां सवाल सिर्फ पद का नहीं, पूरी व्यवस्था का होता है।

डिस्क्लेमर

इस समाचार में उल्लिखित आरोप संबंधित शिक्षकों एवं सूत्रों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, आधिकारिक पुष्टि प्राप्त नहीं हो सकी है, संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

निजी वाहन में सरकारी पेट्रोल खपत! स्वास्थ्य विभाग की पर्ची से खुला बड़ा खेल

20 लीटर पेट्रोल की रसीद सामने आते ही सीएचएमओ कार्यालय पर उठे गंभीर सवाल

-संवाददाता-
एमसीबी,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर विवादों में घिर गया है, इस बार मामला सरकारी मद से निजी वाहन में पेट्रोल भरवाने का सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक साधारण सी पेट्रोल पर्ची ने पूरे कार्यालय की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

20 लीटर पेट्रोल की रसीद ने खोली पोल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय पेट्रोल पंप श्री राम फ्यूल्स से जारी रसीद में झारखंड पंजीयन क्रमांक जेएच 05 बीवी 5038 में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया गया, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह वाहन विभागीय रिकार्ड में सरकारी नहीं, बल्कि निजी वाहन बताया जा रहा है, इसके बावजूद पेट्रोल का भुगतान सरकारी मद से किए जाने की बात सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है।

सीएचएमओ की मुहर और हस्ताक्षर से बढ़ा संदेह

रसीद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की मुहर और हस्ताक्षर दर्ज होने से मामला और गंभीर हो गया है, अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किस नियम के तहत सरकारी धन का उपयोग निजी वाहन में ईंधन भरवाने के लिए किया गया, क्या यह किसी अधिकारी की मौन स्वीकृति से हो रहा था या फिर विभाग में लंबे समय से ऐसा खेल जारी है?

वित्तीय अनियमितता या सरकारी संसाधनों की खुली लूट?

यदि प्रथम दृष्टया सामने आए दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो यह मामला वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ सरकारी नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा, सरकारी वाहनों के लिए स्वीकृत ईंधन का उपयोग निजी गाड़ियों में होना न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, बल्कि यह प्रशासनिक जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है।

क्या लंबे समय से चल रहा है पेट्रोल पर्ची का खेल?

इस एक रसीद के सामने आने के बाद यह आशंका भी गहरा गई है कि कहीं विभाग में इस तरह का खेल लंबे समय से तो नहीं चल रहा, यदि पुराने पेट्रोल बिलों और वाहन लॉगबुक की जांच की जाए, तो और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, सूत्रों का दावा है कि यह सिर्फ एक रसीद नहीं, बल्कि विभाग के भीतर चल रही संभावित अनियमितताओं की एक बड़ी कड़ी हो सकती है।

जांच हुई तो कई जिम्मेदारों के चेहरों से उठ सकता है पर्दा

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं,यदि निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो सिर्फ पेट्रोल पर्ची ही नहीं, बल्कि विभागीय खर्चों के कई और फाइलों से भी चौंकाने

वाले तथ्य सामने आ सकते हैं,दोषियों पर कार्रवाई होती है या मामला दबा दिया जाता है, यह आने वाला समय तय करेगा।

जनता का सवाल - सरकारी पैसा आखिर किसके लिए?

इस खुलासे के बाद आम लोगों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है कि जनता के टैक्स से चलने वाले सरकारी धन का उपयोग आखिर किसके हित में हो रहा है,यदि निजी वाहन में सरकारी पेट्रोल भरवाया जा रहा है,तो यह सीधे-सीधे जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।

भाजपा महामाया मंडल का दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान वर्ग सम्पन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी के महामाया मंडल द्वारा आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान वर्ग उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कुल 8 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें संगठनात्मक विषयों, कार्यपद्धति तथा भाजपा की वैचारिक आधारशिला पर विस्तृत चर्चा की गई। समापन सत्र की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने की,जबकि मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मेजर अनिल सिंह,महापौर मंजूषा भगत तथा सूरजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल गोयल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर आधारित यह प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को सशक्त संगठन निर्माण के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए तथा 'संकल्प से सिद्धि' के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह प्रशिक्षण वर्ग मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के कौशल विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। संगठन की मजबूती के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है और आने वाले समय में यही प्रशिक्षित कार्यकर्ता सरगुजा जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल अध्यक्ष मनोज कंसारी के स्वागत भाषण से हुई। प्रशिक्षण के सभी सत्रों का संचालन मंडल महामंत्री संजीव वर्मा एवं निरंजन राय ने कुशलतापूर्वक किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद हर्ष, जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद विकास पांडेय, मधु चौधाहा, निश्चल प्रताप सिंह, जन्मेजय मिश्रा, राकेश, श्वेता गुप्ता, आकाश गुप्ता, शशिकांत जायसवाल, शिवमंगल सिंह, जितेन सोनी, आलोक दुबे, प्रियंका गुप्ता, विकास गुप्ता, निशांत सिंह, शुभांगी बिहारी, प्रियंका चौबे, सरिता जायसवाल, अविनाश मंडल, सरिता मिश्रा, अल्पना मिश्रा, रवि विश्वकर्मा, जतिन परमार, नंदकिशोर ताम्रकार, पुष्पेंद्र शर्मा, भूपेंद्र सिंह, सतीश सिंह, अविनाश कुशवाहा, सतीश शर्मा, धर्मेंद्र द्विवेदी, मनीष सिंह, सतीश मिश्रा, सिकंदर जायसवाल, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, सुधांशु चौबे, सत्यम सिंह, अजय सारथी, रीना राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सरगुजा कप ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट 10 अप्रैल से

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में 10 से 13 अप्रैल तक सरगुजा कप ऑल इंडिया ओपन फीडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के मार्गदर्शन में सुसीमा वेलफेयर फाउंडेशन, अंबिकापुर द्वारा आयोजित की जा रही है। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के लगभग 10 राज्यों से 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें करीब 90 फीडे रेटेड खिलाड़ी शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता के शीर्ष 5 बोर्डों पर डीजीटी बोर्ड लगाए जाएंगे,जिनके माध्यम से मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट वैश्विक प्लेटफॉर्म Chess.com और Lichess.org पर किया जाएगा। इससे देश-विदेश के दर्शक भी मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 2 लाख निर्धारित की गई है, जिससे खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कई प्रमुख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के अनुष्टुप बिश्वास, महाराष्ट्र के इंद्रजित एवं श्रेयान मजूमदार, गुजरात के इंटरनेशनल मास्टर राहुल संगमा,रेलवे के विनोद शर्मा तथा छत्तीसगढ़ के मोबिन फारुखी शामिल हैं। टूर्नामेंट का संचालन सरोज कुमार वैष्णव के निर्देशन में किया जा रहा है। आयोजन समिति में सुजीत जायसवाल,बी. मनियन,विश्वास तिवारी एवं शेष रतन जायसवाल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं,प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक (चीफ आर्बिटर) अंतरराष्ट्रीय आर्बिटर अनीश अंसारी होंगे।

जशपुर में 2 बच्चों की मौत,तालाब से शव बरामद

-संवाददाता-
जशपुर,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां बीते दिन से लापता दो मासूम बच्चों की लाश तालाब में तैरती हुई मिली है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र के बिसबहरी गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक बच्चों की पहचान गोल्डी टोप्पो (7 वर्ष) और अनीस टोप्पो (8 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार,दोनों बच्चे शनिवार शाम से लापता थे। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की,लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो बगीचा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के बाद पुलिस लगातार बच्चों की खोजबीन में लगी हुई थी। इसी बीच आज रविवार को गांव के पास स्थित एक तालाब में दोनों बच्चों के शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,दोनों बच्चे तालाब में नहाने गए हुए थे,तभी यह हादसा हुआ। हालांकि, मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर यह घटना कैसे हुई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कुमेली जंगल में जुए का कथित साम्राज्य

'न बंद हुआ, न बंद होगा' के दावे से मचा हड़कंप

- सूरजपुर में जुए का नेटवर्क बेखौफ : खबरों के बाद भी जारी खेल,सिस्टम पर उठे सवाल...
- जंगल में 'जुआ दरबार': 4 घंटे का खेल,लाखों के दांव और कार्रवाई पर सवाल...
- खबर छापते रहो...जुआ चलता रहेगा...कुमेली में कथित जुआ नेटवर्क की खुली चुनौती...
- कानून को चुनौती या सिस्टम की नाकामी ? कुमेली में जुए के कथित नेटवर्क से उठे बड़े सवाल...
- जंगल में संगठित जुआ नेटवर्क की चर्चा : तय समय,तय सिस्टम और कथित संरक्षण का खेल...

कथित संरक्षण और सिस्टम की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

-शमरोज खान-
सूरजपुर,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

जिले में अवैध जुए के कथित नेटवर्क को लेकर हालात अब सामान्य चर्चा से आगे बढ़कर खुली चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं,कुमेली पर्यटन स्थल और आसपास के जंगल क्षेत्रों में जुआ संचालन को लेकर स्थानीय स्तर पर यह तक कहा जा रहा है कि पत्रकार खबर छापते रहें,जुआ न बंद हुआ है और न बंद होगा।

सूत्रों के अनुसार यह बयान कथित तौर पर जुआ संचालित करने वाले लोगों द्वारा दिया जा रहा है, हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही जानकारियों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार पहले जुए के कई ठिकाने शहर के आसपास सक्रिय थे,जहां समय-समय पर पुलिस कार्रवाई भी होती थी और मामले सुर्खियों में आते थे,लेकिन जैसे-जैसे निगरानी बढ़ी,वैसे-वैसे जुआ संचालित करने वालों ने अपनी रणनीति बदल ली,अब कथित तौर पर जुए का यह नेटवर्क शहर से दूर जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में शिफ्ट हो गया है, कुमेली पर्यटन स्थल के आसपास और सूरजपुर-कोरिया सीमा के पास स्थित माजा क्षेत्र को इसका नया केंद्र बताया जा रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि जंगल का चयन इसलिए किया गया है ताकि आवाजाही कम रहे, बाहरी लोगों की नजर न पड़े और किसी भी कार्रवाई की स्थिति में बच निकलना आसान हो,कुछ लोग इसे व्यंग्य में जंगल मॉडल कह रहे हैं।

घटती-घटना
कोरिया- सूरजपुर समाचार
अम्बिकापुर,शनिवार 14 मार्च 2026
5
सूरजपुर में शाम ढलते ही सजता
जुए का 'दरबार'
जंगल और सीमावर्ती इलाकों में बड़े जुआ खेल की चर्चा
जंगल में जुआ, शहर में सन्नाटा
'बुक' में दर्ज होता है लाखों का हिसाब
कुछ नाम बार-बार चर्चा में...
अब देखना होगा...
विशेष खोजी रिपोर्ट
कथित बंटवारे में कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी चर्चा में
रामानुजनगर थाना और साइबर शाखा पर सवाल
एस कुमार की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं
बड़े अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल
सिस्टम पर उठता बड़ा सवाल
निष्पक्ष जांच की मांग

तय समय में चलता है खेल : 4 घंटे का 'जुआ शिफ्ट सिस्टम'

सूत्रों के मुताबिक जुए का यह कथित संचालन पूरी तरह समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है, शाम लगभग 4 बजे से शुरुआत,रात 8 बजे तक समापन, इन चार घंटों के भीतर लाखों रुपये के दांव लगने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग इसे जुआ शिफ्ट सिस्टम की संज्ञा दे रहे हैं,जहां समय, स्थान और संचालन सभी पहले से तय रहते हैं।

'बुक सिस्टम' से चलता है पूरा नेटवर्क

बताया जा रहा है कि यह केवल मौके पर बैठकर ताश खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक व्यवस्थित आर्थिक तंत्र भी सक्रिय है, बुक के माध्यम से दांव दर्ज किए जाते हैं, दूर बैठे लोग भी इसमें शामिल होते हैं,हार-जीत का पूरा हिसाब व्यवस्थित रूप से रखा जाता है,इससे यह संकेत मिलता है कि जुए का यह कथित नेटवर्क एक संगठित संरचना के रूप में काम कर रहा है, हालांकि इन बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कुछ नामों की चर्चा : जिम्मेदारियों का बंटवारा

स्थानीय स्तर पर इस कथित नेटवर्क से जुड़े कुछ नाम बार-बार चर्चा में आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुमेली क्षेत्र में संचालन की जिम्मेदारी कथित रूप से शमशेर के पास बताई जा रही है,माजा क्षेत्र में एस कुमार अपनी टीम के साथ सक्रिय बताए जा रहे हैं, इसके अलावा बबलू,विवेक,राजकुमार और संजू जैसे नाम भी चर्चा में हैं,हालांकि इन सभी नामों और आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही चर्चाओं ने मामले को गंभीर बना दिया है।

जुआ बंद नहीं होगा...खुलेआम दावे से बढ़ी चिंता

स्थानीय लोगों का दावा है कि जुआ संचालित करने वाले कुछ लोग खुलेआम यह कहते सुने जा रहे हैं— पत्रकारों को जितना खबर छापना है छाप लें,जुआ न बंद हुआ है और न बंद होगा। यह भी कहा जा रहा है कि जब भी खबरें प्रकाशित होती हैं,तो कुछ दिनों के लिए गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, लेकिन 5-6 दिन बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, यदि ये दावे सही हैं,तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जा रही है।

पुलिस और साइबर शाखा की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप स्थानीय पुलिस थाना और साइबर शाखा को लेकर लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों का दावा है कि जब तक संबंधित टीम में कुछ अधिकारी मौजूद हैं,तब तक यह गतिविधियां जारी रहेंगी। यहां तक कि यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा नेटवर्क कथित संरक्षण में संचालित हो रहा है,हालांकि इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कथित लेन-देन और बंटवारे की चर्चा

सूत्रों के अनुसार इस कथित जुए के नेटवर्क में रोजाना बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन-देन होता है, कुछ चर्चाओं में यह भी सामने आ रहा है कि इस रकम का एक हिस्सा अलग-अलग स्तरों पर बांटा जाता है,हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह की बातें सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है।

प्रशासनिक चुप्पी बनी बड़ा सवाल

लगातार सामने आ रही चर्चाओं और आरोपों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई स्पष्ट और ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां चल रही हैं और कार्रवाई नहीं हो रही,तो यह स्थिति चिंताजनक है और इससे गलत संदेश जाता है।

निष्पक्ष जांच की मांग तेज

क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है, उनका कहना है कि जुए के इस कथित नेटवर्क की गहराई से जांच हो,यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए,किसी भी स्तर पर संरक्षण देने वालों को बख्शा न जाए।

क्या रुकेगा 'जंगल का जुआ नेटवर्क'?

सूरजपुर जिले में जुए के इस कथित नेटवर्क ने केवल कानून व्यवस्था ही नहीं,बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है,अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या यह नेटवर्क वास्तव में खत्म होगा, या फिर न बंद हुआ है,न बंद होगा जैसे दावे ही हकीकत बनते रहेंगे? फिलहाल, पूरे जिले की निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

मनेन्द्रगढ़ में लाखों की चोरी का अब तक खुलासा नहीं,पुलिस और साइबर सेल पर उठे सवाल

रेलवे कॉलोनी चोरी कांड अनसुलझा : महीनों बाद भी पुलिस खाली हाथ,क्या मोबाइल खोजने तक सीमित है साइबर टीम? बड़ी चोरी में नहीं मिल रहा सुराग

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,05 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच मनेन्द्रगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले में महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है,लेकिन अब तक मामले का कोई ठोस खुलासा नहीं हो सका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी शैलेष चटर्जी, निवासी रेलवे कॉलोनी (वार्ड क्रमांक 03), के सूने मकान में 1 अक्टूबर 2025 की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला था, घटना के समय परिवार दुर्गा पूजा पंडाल में गया हुआ था,जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया।

सोने-चांदी के जेवरात ले उड़े चोर

चोरों ने घर में रखी अलमारी और दीवान को खंगालते हुए सोने-चांदी के कीमती आभूषण पार कर दिए,इनमें सोने का लॉकेट,चेन, अंगूठी,मंगलसूत्र और चांदी के अन्य जेवर शामिल थे,चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई थी।

महीनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली

घटना को कई महीने बीत चुके हैं,लेकिन अब तक न तो आरोपियों का पता चल सका है

और न ही चोरी गया सामान बरामद हो पाया है,इस देरी ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

साइबर टीम की भूमिका पर उठ रहे सवाल

क्षेत्र में चर्चा है कि साइबर सेल की सक्रियता केवल गुम हुए मोबाइल फोन खोजने तक सीमित रह गई है,बड़े चोरी के मामलों में तकनीकी साक्ष्य जुटाने और अपराधियों तक पहुंचने में अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आ रही है।

पुलिस और साइबर सेल के बीच समन्वय की कमी

सूत्रों के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ थाना पुलिस और साइबर सेल के बीच तालमेल की कमी भी इस मामले के लंबित रहने का बड़ा कारण है, यदि तकनीकी जांच और जमीनी स्तर की कार्रवाई में बेहतर समन्वय होता,तो अब तक आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था।

संदिग्धों से दोबारा पूछताछ की जरूरत

सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले जिन संदिग्धों से पूछताछ की गई थी,उनसे दोबारा कड़ाई से पूछताछ की जाए तो मामले में अहम सुराग मिल सकते हैं, अक्सर शुरुआती जांच में छूटी कड़ियां दोबारा जांच में सामने आती हैं,जिससे केस सुलझाने में मदद मिलती है।

पुलिस के सामने साख बचाने की चुनौती

अब यह मामला मनेन्द्रगढ़ पुलिस के लिए साख का विषय बन गया है, यदि जल्द ही मामले का खुलासा नहीं होता,तो जनता का भरोसा और कमजोर हो सकता है।

पीड़ित परिवार की गुहार

पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।

क्या बदलेगी पुलिस की रणनीति?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनेन्द्रगढ़ पुलिस अपनी जांच रणनीति में बदलाव लाकर इस मामले को सुलझा पाएगी या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0-/अ-27/2024-25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुमताज अहमद आ. स्व. मोहम्मद इब्राहिम निवासी नवापारा,ग्रामीण बैंक के पास,अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 2445 / 10 रकबा 0.032 हे भूमि को उभयपक्ष के मध्य में 1/4 अंश में बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 27/04/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक:- 30/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) तहसीलदार
अम्बिकापुर (छ.ग.)

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/....../अ-6 /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका अनिता सोनी आ.स्व. कृष्ण सोनी, उम्र 45 वर्ष, जाति सोनार, निवासी ग्राम कौवाडांड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के पिता कृष्ण प्रसाद सोनी आ.स्व. गणेश सोनी स्वामित्व व आधिपत्य की नगर अम्बिकापुर मोहल्ला कोवाडांड स्थित नजूल भूमि प्लाट नंबर 1480/1, 1478 / 2 रकबा क्रमश- 0.03, 0.02 एकड़ भूमि स्थित है। भूधारक कृष्ण सोनी की मृत्यु दिनांक 27.05.1999 को हो गई है। अतः कृष्ण सोनी के मृत्यु उपरांत उक्त भूमि से उनका नाम विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदिका द्वारा भूधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20/04/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सील) नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुसुम मिश्रा पत्नी सुरेश कुमार मिश्रा निवासी जनपदपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 352/12 रकबा 0.014 हे0 भूमि को अनावेदक आयांश उपाध्याय आ0चन्द्रशेखर उपाध्याय ना. बा. द्वारा माता एवं वली अर्चना मिश्रा पुत्री सुरेश कुमार मिश्रा पत्नी चन्द्रशेखर उपाध्याय निवासी वार्ड नंबर 17 जनपदपारा अम्बिकापुर के पास दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 22.04.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 01/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) तहसीलदार
अम्बिकापुर (छ.ग.)

राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग या सुनियोजित जमीन हड़प कांड?

सूरजपुर रजिस्ट्री महाघोटाला: पुलिस अब सक्रिय

‘नशे वाले वीडियो’ की तलाश में टीम, पार्षद और दामाद से पूछताछ की तैयारी

शुरुआत से अब तक की कहानी

76 वर्षीय रामचरित साहू ने अपनी बेटियों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। 5 बेटियां और दामाद मुख्य संदिग्ध थे। पार्षद पर माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप। जमीन।

जमीन पर कब्जा:

पैरे पसे भारी कमी

अब उस कथित ‘नशे वाले

सूरजपुर में पार्षद, साहू बोरवेल संचालक और दस्तावेज लेखक पर गंभीर आरोप

कागज़ में खाली जमीन,हकीकत में करोड़ों का निर्माण...नशे में सहमति,बेटी को बनाया मोहरा, 80 डिसमिल जमीन पर कब्जे का आरोप

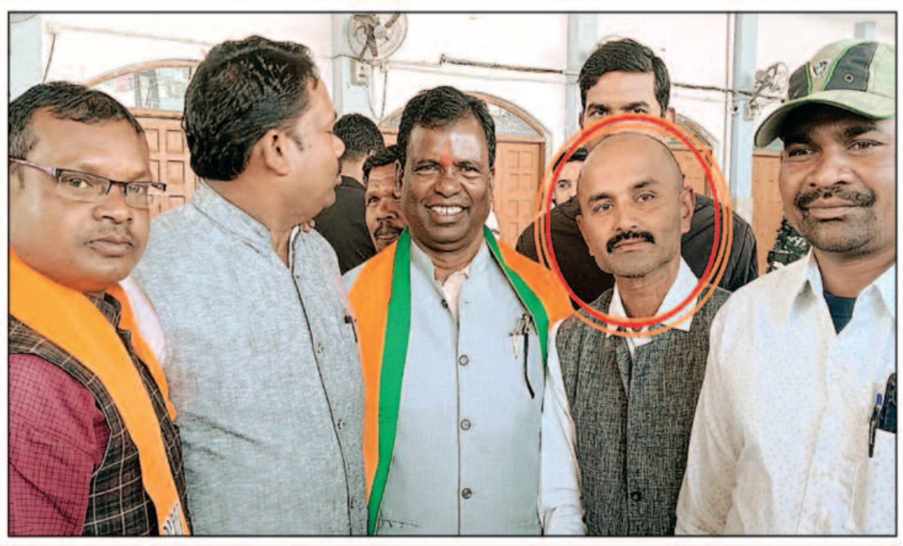

-शमरोज खान-

सूरजपुर,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। क्या लोकतंत्र में सत्ता से नजदीकी और नेताओं के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें किसी को कानून से ऊपर खड़ा कर देती हैं? क्या राजनीतिक पहचान इतनी ताकतवर हो सकती है कि वह किसी आम नागरिक की जमीन, अधिकार और न्याय–तीनों को निगल जाए? सूरजपुर जिले के मानपुर से सामने आया ताजा मामला इन्हीं तीखे सवालों को जन्म देता है,जहां आरोप है कि जनता के वोट से चुना गया एक पार्षद उसी जनता के एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने के गंभीर आरोपों में घिर गया है,इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आती है कि एक व्यक्ति की नशे की लत, जो उसकी निजी कमजोरी थी,उसे ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया गया,आरोप है कि उसी वार्ड के पार्षद,एक बोरवेल संचालक और एक दस्तावेज लेखक ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना, जिसमें पीड़ित अपनी ही जमीन से बेदखल हो गया, बताया जा रहा है कि लगभग 80 डिसमिल जमीन को पहले बेटी के नाम रजिस्ट्री कराई गई, फिर उसी बेटी को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन का हिस्सा पार्षद और अन्य लोगों के नाम कर दिया गया। इससे भी अधिक गंभीर आरोप यह है कि जिस जमीन पर पहले से करोड़ों का निर्माण मौजूद था,उसे कागज़ों में खाली भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई,यह मामला केवल एक जमीन विवाद नहीं रह जाता,बल्कि यह सत्ता,प्रभाव,दस्तावेजी प्रक्रिया और कथित मिलीभगत के खतरनाक मेल का उदाहरण बनकर उभरता है, स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि संबंधित पार्षद की मंत्री, विधायक और बड़े नेताओं से नजदीकी है,और यही कारण है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई,ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है–क्या लोकतंत्र में आम नागरिक के अधिकार उसकी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत के सामने इतने कमजोर हो चुके हैं कि उसकी जमीन भी सुरक्षित नहीं रही? सूरजपुर का यह मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता, कानून की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा बन चुका है। बता दे की छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सामने आया जमीन विवाद अब एक साधारण पारिवारिक मतभेद से कहीं आगे बढ़कर एक संभावित संगठित जमीन हड़प प्रकरण के रूप में उभर रहा है,मानपुर निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके ही वार्ड के पार्षद, स्थानीय बोरवेल संचालक और दस्तावेज लेखक ने मिलकर उसकी लगभग 80 डिसमिल जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया,इस पूरे मामले में भाजपा पार्षद राजेश साहू,बोरवेल संचालक राधाकृष्ण साहू और दस्तावेज लेखक सलीम अली की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी नशे की लत को उसकी कमजोरी बनाकर,उसी का फायदा उठाते हुए यह पूरा खेल रचा गया।

क्या राजनीतिक पहुंच बन गई ‘जमीन हड़पने का लाइसेंस’? सूरजपुर मामला चर्चा में...

जिसके वोट से जीते,उसी की जमीन ही ले उड़े! सूरजपुर में पार्षद पर गंभीर सवाल...

नशे की मजबूरी का फायदा,बेटी को बनाया मोहरा–80 डिसमिल जमीन पर कब्जे का आरोप...

राजनीतिक रसूख या जमीन हड़प कांड? सूरजपुर में पार्षद पर गंभीर आरोप...

कागज़ में खाली जमीन,हकीकत में कब्जा–सूरजपुर में बड़ा रजिस्ट्री खेल उजागर...

पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल : बेटी के नाम जमीन,फिर पार्षद के कब्जे का आरोप...

नेताओं संग फोटो,जमीन पर कब्जा? सूरजपुर में पार्षद पर उठे बड़े सवाल...

मामले की शुरुआत : विश्वास से षड्यंत्र तक

पीड़ित के अनुसार,शुरुआत में मामला पारिवारिक स्तर का प्रतीत हुआ, जहां उसकी बेटी को आगे कर जमीन के कागज़ तैयार कराए गए,लेकिन धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह केवल एक सामान्य रजिस्ट्री नहीं,बल्कि एक बहुस्तरीय योजना थी,जिसमें स्थानीय स्तर पर कई लोगों की भूमिका जुड़ी हुई थी, आरोप है कि पीड़ित को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर स्थिति–विशेषकर नशे की हालत–में रखते हुए उससे ऐसे दस्तावेजों पर सहमति ली गई,जिनके दूरगामी परिणाम उसे समझाए ही नहीं गए।

कागज़ बनाम हकीकत : खाली जमीन का सच

इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई,उसे दस्तावेजों में खाली भूमि दर्शाया गया,जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग बताई जा रही है,स्थानीय सूत्रों और पीड़ित के अनुसार,उस जमीन पर पहले से दुकान और अन्य निर्माण मौजूद थे, जो मुख्य सड़क से जुड़े होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान माने जाते हैं, यदि यह आरोप सही हैं,तो यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है,जिसमें जानबूझकर जमीन की वास्तविक स्थिति छुपाई गई,ताकि उसकी कीमत कम आंकी जा सके और बाद में उसे हड़पना आसान हो।

नशे में सहमति : वैध या जबरन?

मामले का सबसे संवेदनशील पहलू वह वीडियो है,जिसमें पीड़ित व्यक्ति जमीन हस्तांतरण की सहमति देता हुआ दिखाई देता है,हालांकि, पीड़ित का दावा है कि यह वीडियो उसकी नशे की हालत में बनवाया गया,यह सवाल यहां बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या नशे में दी गई सहमति को वैध माना जा सकता है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है और उस समय उससे सहमति ली जाती है,तो वह वैध सहमति नहीं मानी जाती और उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है,इस दृष्टि से देखा जाए तो यह वीडियो एक सबूत कम और एक संभावित षड्यंत्र का हिस्सा अधिक प्रतीत होता है।

बेटी के नाम रजिस्ट्री,फिर पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल

आरोपों के अनुसार,इस पूरे मामले में सबसे पहले पीड़ित की बेटी को केंद्र में लाया गया, जमीन को उसके नाम पर रजिस्ट्री कराया गया,जिसके बाद उसी बेटी से का हिस्सा अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित कर दिया गया, बताया जा रहा है कि पूरी जमीन पहले बेटी के नाम की गई, फिर लगभग 16 डिसमिल जमीन पार्षद राजेश साहू और राधाकृष्ण साहू के नाम कर दी गई, यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित रणनीति की ओर संकेत करता है,जिसमें पहले परिवार के भीतर से जमीन निकाली गई और फिर बाहरी लोगों के नाम कर दी गई।

प्रशासन की भूमिका : कार्रवाई या मौन?

इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू प्रशासन की अब तक की निष्क्रियता मानी जा रही है,पीड़ित द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है,क्या जांच प्रारंभ की गई है? क्या संबंधित अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया? क्या दस्तावेजों की सत्यता की जांच हुई? या मामला अभी भी फाइलों में दबा हुआ है?

पारिवारिक विवाद से संगठित खेल तक

शुरुआत में यह मामला एक पारिवारिक विवाद जैसा प्रतीत हो सकता था, लेकिन जैसे-जैसे तथ्य सामने आए,यह स्पष्ट होता गया कि इसमें कई स्तरों पर मिलीभगत की आशंका है,इसमें शामिल हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि,स्थानीय कारोबारी,दस्तावेजी प्रक्रिया से जुड़े लोग और अन्य सहयोगी यह पूरा घटनाक्रम एक संगठित जमीन हड़पने के मॉडल की ओर संकेत करता है,जिसमें कमजोर व्यक्ति को निशाना बनाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है।

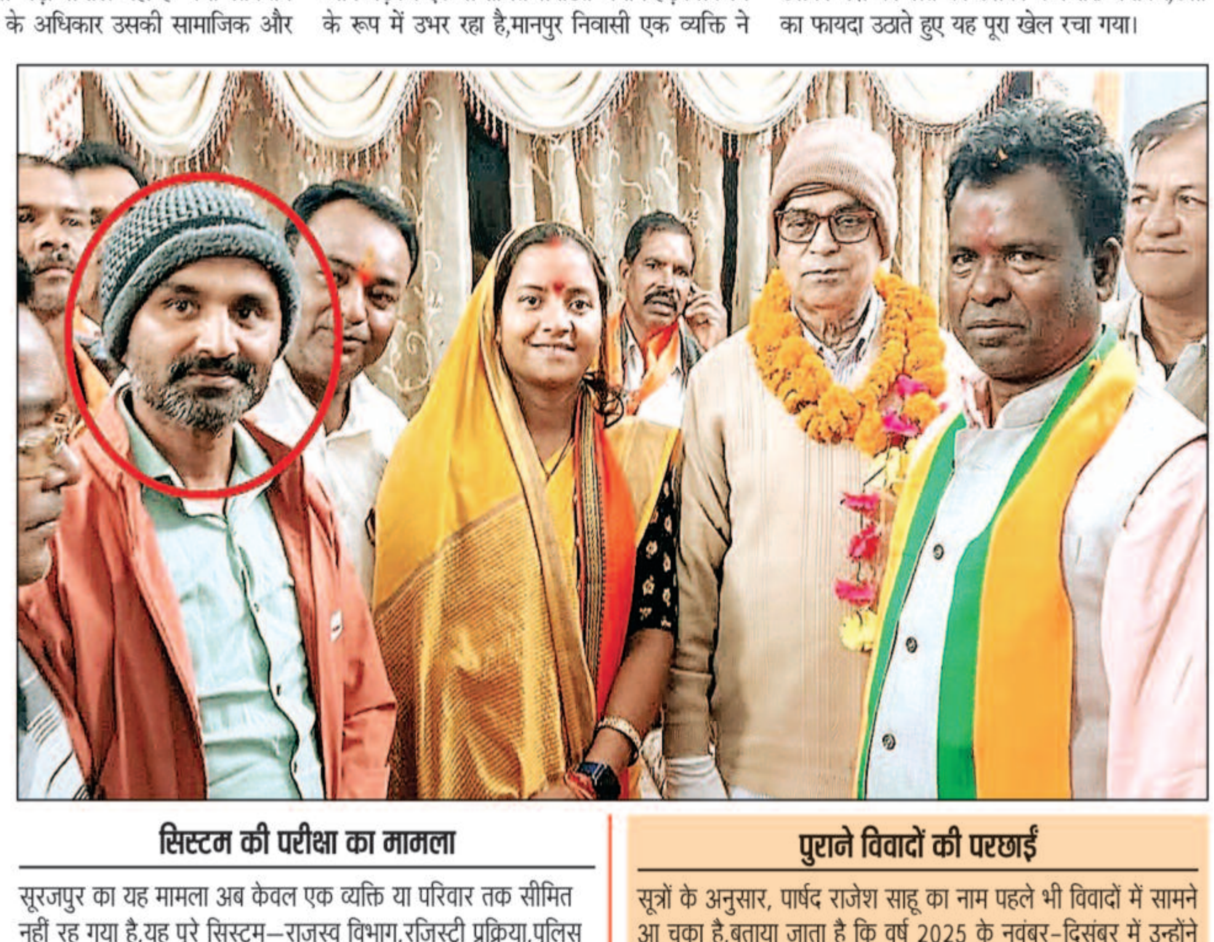

सिस्टम की परीक्षा का मामला

सूरजपुर का यह मामला अब केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रह गया है,यह पूरे सिस्टम–राजस्व विभाग,रजिस्ट्री प्रक्रिया,पुलिस प्रशासन और राजनीतिक ढांचे–की परीक्षा बन चुका है, यहां कागज़ कुछ और कह रहा है और जमीन की हकीकत कुछ और,यदि आरोप सही साबित होते हैं,तो यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता मानी जाएगी।

पुराने विवादों की परछाईं

सूत्रों के अनुसार, पार्षद राजेश साहू का नाम पहले भी विवादों में सामने आ चुका है,बताया जाता है कि वर्ष 2025 के नवंबर-दिसंबर में उन्होंने एक खनिज अधिकारी के साथ कार्रवाई के दौरान विवाद किया था, यह मामला एक ट्रैक्टर गिट्टी से जुड़ा था,जिसमें दस्तावेजों की अनुपस्थिति के बावजूद उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया,हालांकि, बाद में मामला उनके खिलाफ जाता देख उन्होंने पीछे हटना ही उचित समझा।

कानूनी और नैतिक प्रश्न

क्या नशे में ली गई सहमति वैध है?

क्या निर्माण छुपाकर रजिस्ट्री करना अपराध नहीं?

क्या बिना भुगतान के जमीन का हस्तांतरण संभव है?

क्या राजनीतिक प्रभाव कानून से ऊपर हो सकता है?

इन सवालों के जवाब केवल इस मामले के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

डिस्क्लेमर

इस समाचार में उल्लिखित सभी आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, समाचार का उद्देश्य उपलब्ध तथ्यों एवं आरोपों को प्रस्तुत करना है।

भुगतान का रहस्य : जमीन गई,पैसा नहीं मिला

जमीन के किसी भी वैध लेन-देन में भुगतान सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है,लेकिन इस मामले में पीड़ित का दावा है कि उसे किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, यदि यह दावा सत्य है,तो यह मामला और अधिक गंभीर हो जाता है, क्योंकि बिना भुगतान के रजिस्ट्री होना या उसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड न होना सीधे-सीधे धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है,यह स्थिति पूरे लेन-देन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है और यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया को जानबूझकर अपारदर्शी रखा गया।

दस्तावेज लेखक की भूमिका : जानकारी थी या अनदेखी?

इस पूरे मामले में दस्तावेज लेखक सलीम अली की भूमिका भी जांच के दायरे में है,वह उसी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है,जहां यह जमीन स्थित है,ऐसी स्थिति में यह मानना कठिन है कि उसे जमीन की वास्तविक स्थिति–निर्माण,लोकेशन और मूल्य–की जानकारी नहीं रही होगी,और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके भाई स्वयं अधिवक्ता हैं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इस पूरे लेन-देन में कानूनी सलाह नहीं ली गई,या फिर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई?

राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का आरोप

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि पार्षद राजेश साहू की राजनीतिक पहुंच मजबूत है और उनके मंत्री,विधायक तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं,बताया जाता है कि इन संबंधों और तस्वीरों का उपयोग प्रभाव दिखाने के लिए किया जाता है,सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किया गया? क्या यही कारण है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई?

एडल्ट साइट पर मेरी तस्वीर...

15 साल की उम्र में जाह्नवी कपूर के साथ हुई थी ये चौंकाने वाली घटना

जाह्नवी कपूर ने अपने टीनएज के दिनों की एक परेशान करने वाली घटना को याद किया और बताया कि कैसे उनकी डीपफेक तस्वीरें आज भी उन्हें प्रभावित करती हैं।

जाह्नवी कपूर हमेशा से नेपोटिज्म के दबाव, सामाजिक मुद्दों और लोगों की नजर में रहने के अपने निजी अनुभवों के बारे में खुलकर बात करती रही है। हाल ही में उन्होंने ऑनलाइन वायरल हो रही अपनी एआई जनरेटेड तस्वीरों से जुड़े कुछ गहरे मुद्दों पर बात की। इसे ऑनलाइन दुनिया का एक जोखिम मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश के बावजूद, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें अब भी इन बातों से बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। एक इंटरव्यू में जाह्नवी कपूर ने अपने टीनएज के दिनों का एक परेशान करने वाला अनुभव साझा किया।

एडल्ट साइट पर देखी अपनी ही तस्वीर

उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 15 साल की थीं,तब उन्हें एक पोर्न साइट पर अपनी मॉर्फ्ड (बदली हुई) तस्वीर मिली थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वह डीपफेक था या नहीं, लेकिन वह कुछ वैसा ही था। मैंने एक पोर्न साइट पर अपनी तस्वीर देखी थी। हमारे स्कूल में आईटी की क्लास होती थी और लड़के मजे के लिए उन साइट्स पर जाते थे। वहां मेरी तस्वीरें भी थीं और यह सब स्कूल के दिनों की बात है। इसलिए,वह एक बहुत ही अजीब अनुभव था। उन्होंने आगे कहा, एक समय ऐसा भी आया, जब मुझे लगा कि यही वह कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीजों में नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। जाह्नवी कपूर ने बताया कि एआई से बनी उनकी तस्वीरों का उन पर कितना गहरा असर पड़ता है।

प्रोफेशनल करियर पर पड़ता है फर्क

उन्होंने आगे कहा, ये तस्वीरें इस तरह से फैलाई जाती हैं, जैसे इन्हें मैंने खुद ही शेयर किया हो। इससे लोगों के मन में एक खास तरह की छवि बन जाती है। अगर कल को मैं किसी डायरेक्टर से कहूं कि मैं कोई खास तरह के कपड़े पहनने में सहज महसूस नहीं कर रही हूं, तो कोई भी उन तस्वीरों को दिखाकर कह सकता है, लेकिन आपने तो पहले भी ऐसा किया है।

जाह्नवी ने निकाला ये तरीका

जाह्नवी ने कहा,जाहिर है, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन समय के साथ इस स्थिति से निपटने के तरीके ढूंढ़ लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिकायत करने के लिए मेरी आवाज में अभी उतनी ताकत नहीं है। लोगों का रवैया कुछ ऐसा है। तुम्हें जिंदगी में इतना कुछ मिला है, तो थोड़ा-बहुत तो सहना ही पड़ेगा,शिकायत मत करो। अगर मैं शिकायत करूंगी,तो लोग मेरी ही आलोचना करेंगे,और इससे मेरा असली मुद्दा ही कहीं पीछे छूट जाएगा।
जाह्नवी कपूर पिछली बार सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आई थीं। इसके बाद वे राम चरण के साथ पेद्दी में नजर आएंगी।

रेखा के जीजाजी हैं हिंदी सिनेमा के खूंखार विलेन

एक्ट्रेस की छोटी बहन से की है शादी, कंजी आंख देख सहम जाते थे दर्शक

रेखा बॉलीवुड की एवरग्रीन सुपरस्टार हैं,आज भले ही रेखा कम ही फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन उनका स्टारडम आज भी कायम है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीजाजी भी 80-90 के दशक के टॉप खलनायक रहे हैं
बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा ने अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर लाखों दिलों पर राज किया और आज भी उनकी लोकप्रियता और स्टारडम कायम है। लेकिन, क्या आप रेखा के जीजाजी के बारे में जानते हैं? रेखा के जीजाजी भी फिल्मी दुनिया के जाने-माने कलाकार हैं और एक समय पर बॉलीवुड के टॉप विलेन थे। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे खलनायकों की परंपरा आगे बढ़ाने वाले अभिनेता तेज स्प्रू की,जिनकी कंजी आंखों को देखकर दर्शक एक समय पर सहम जाते थे। तेज स्प्रू कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे,लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय की दुनिया तक ले आई। उन्होंने फिल्मी दुनिया में हीरो बनकर एंट्री ली,लेकिन खलनायक के किरदारों ने उन्हें पहचान दिलाई।

इन फिल्मों में निभाए यादगार रोल

तेज स्प्रू ने 'त्रिदेव,'मोहरा जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल निभाए और अपने प्रभावशाली अभिनय से खास छाप छोड़ने में सफल रहे। तेज स्प्रू का जन्म 5 अप्रैल 1955 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम डीके स्प्रू यानी दया किशन स्प्रू और मां का नाम हेमावती था। डीके स्प्रू भी अपने दौर के बड़े कलाकार था। वहीं तेज स्प्रू ने अपनी कंजी आंखों से दर्शकों को खूब

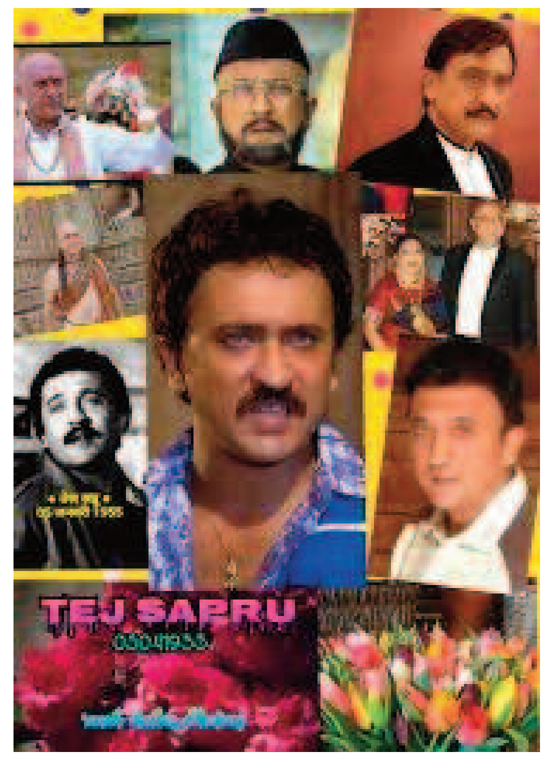

डराया। उन्होंने अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और ज्यादातर निगेटिव रोल ही प्ले किए।

रेखा की छोटी बहन से की है शादी

बता दे,तेज स्प्रू रिश्ते में बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा के जीजाजी हैं। उन्होंने रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी से शादी की है। लेकिन, कम ही लोग जानते हैं कि शुरुआत में रेखा तेज सप्रू के साथ अपनी बहन धनलक्ष्मी के रिश्ते के खिलाफ थीं। इसका खुलासा खुद तेज सप्रू ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान तेज स्प्रू ने बताया था कि रेखा नहीं चाहती थीं कि उनकी शादी धनलक्ष्मी से हो,क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे और उन्हें डर था कि धनलक्ष्मी के साथ कुछ गलत न हो। लेकिन, रेखा की मां पुष्पावली चाहती थीं कि तेज उनके घर के दामाद बनें। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था- रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। मेरी दूसरी शादी धनलक्ष्मी से लिखी थी और मैंने अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर उनसे शादी कर ली।

क्रिकेटर बनना चाहते थे तेज स्प्रू

तेज स्प्रू एक समय पर क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे। उनकी अभिनय में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन किस्मत उन्हें अभिनय तक खींच लाई। तेज स्प्रू ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के बारे में बात करते हुए बताया कि एक दिन उनके पिता ने बताया कि 'सुरक्षा फिल्म के निर्देशक रविकांत एक नए चेहरे की तलाश में हैं और तेज सप्रू अपने जीजा राकेश नाथ के साथ डायरेक्टर से मिलने चले गए। जैसे ही डायरेक्टर ने उन्हें देखा तो बोले- यही मेरा हीरो होगा। और ऐसे उनके करियर की शुरुआत हुई।

रामायण में एआई के सीन्स के आरोपों पर भड़का एक्टर

सीन दिखाकर दे डाला सबूत, ट्रोल्स को फिर होना पड़ा शर्मशार

रामायण का टीजर रिलीज होते ही फिल्म सुर्खियां बटोरने लगी थी। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक सीन को लेकर एआई के भी आरोप लगाए थे। अब एक्टर ने इन आरोपों को पूरी तरह फर्जी साबित कर दिया है। रणबीर कपूर स्टारर रामायण का बीते दिनों टीजर रिलीज किया गया था जिसमें उनका पहला लुक भी सामने आया था। साथ ही फिल्म में रणबीर कपूर के डबल रोल की भी बातों की पुष्टि हो गई है। लेकिन फिल्म का एक सीन अपने परफेक्शन के लिए ही विवादों में घिर गया। रणबीर कपूर का एक सीन है जिसमें वे अयोध्या में अपनी राज्य की जनता के बीच से गुजरते हैं। लेकिन इस सीन को देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इस सीन को एआई से बनाने के आरोप लगा डाले। अब इसी सीन के एक एक्टर ने इन आरोपों पर करारा तमाचा मारकर सच्चाई बताई है। एक्टर ने सेट पर होने और सीन पूरी तरह शूट होने की भी पुष्टि की है।

एआई के लगाए थे आरोप

गुरुवार को रामायण के टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया और एक खास पल ने सबका ध्यान खींचा। इसलिए नहीं कि प्रशंसकों को वह पसंद आया, बल्कि इसलिए कि कई लोगों को उसमें कुछ गड़बड़ी नजर आई। अयोध्या के एक दृश्य में रणबीर कपूर के गुजरते ही एक सहायक अभिनेता की पगड़ी का रंग नीले से बैंगनी होता हुआ दिखाई दिया। कई लोगों को लगा कि यह दृश्य आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माताओं की जमकर आलोचना की। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में रहे साकेत नाम के एक्टर ने इसकी सच्चाई बताई है। साकेत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और उस सीन में खुद के होने की पुष्टि भी की है। इतना ही नहीं साकेत ने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने ये सीन शूट किया था। इस सीन में सब कुछ वास्तविक है और रणबीर कपूर के साथ नजर आ रहा पूरा क्राउड रियल है।

शादीशुदा एक्टर का रहा अफेयर

शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में पीयूष ने कहा कि वह पहले एक अच्छे पति नहीं थे। उन्होंने कहा, अब मैं एक अच्छा पति हूं..पहले नहीं था। उस समय मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था और शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप 20 साल की उम्र में प्यार में पड़ते हैं तो उसमें कोई तर्क नहीं होता...यही उसकी खूबसूरती है, लेकिन 35 साल के बाद आप उस इंसान से प्यार करते हैं जो आपके साथ बूढ़ा होने को तैयार हो। प्यार की परिभाषा उस महिला से तय होती है जो आपके साथ बूढ़ी होने को तैयार हो और उसने यह स्वीकार किया कि वह मेरे साथ बूढ़ी होगी। पीयूष मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें अपनी शादी को सच में स्वीकार करने में कितना समय लगा। उन्होंने इस दौरान कहा, मुझे यह समझने में लगभग 15 साल लग गए कि वह मेरी पत्नी है। उससे पहले वह बस एक ऐसी औरत थी,जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया... मेरे लिए खाना बनाया और घर की देखभाल की। उसके अलावा मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। पीयूष ने आगे बताया कि वह एक समय भावनात्मक रूप से अलग-थलग रहते थे। उन्होंने खुद को बहुत रूखा और असामाजिक बताया। इस दौरान अपनी पत्नी प्रिया के बारे में बात करते हुए,पीयूष ने अपनी शादी को बचाए रखने का श्रेय उनकी ताकत और धैर्य को दिया। पीयूष मिश्रा ने कहा, वह मुझसे प्यार करती थी। वह मेरे लिए घर से भाग आई थी और अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की थी...उसने कहा था कि वह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफ की और उनकी कुर्बानियों को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो बिना देर किए पत्नी से माफी मांगी और इस दौरान वह रो पड़े थे।

खेल समाचार

गुजरात टाइटन्स पर जीत से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान बराक का आत्मविश्वास बढ़ा : इरफान पठान

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स को 6 रन से हराकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। मैच 4 अप्रैल को अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ लगातार दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने कहा कि इस जीत से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान बराक का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। उन्होंने कहा,कल राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच हुआ मैच इस आईपीएल सीजन का अब तक का सबसे अच्छा मैच था। टीम के कप्तान के तौर पर यह रियान बराक के लिए बहुत अहम मैच था। इरफान पठान ने रियान बराक के निर्णायक फैसले की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कप्तान मैच का आखिरी ओवर सबसे अनुभवी गेंदबाज को देता है, लेकिन इस मैच में रियान बराक ने 19वां ओवर जोफ्रा आर्चर को दिया। आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन दिए। यदि उन्होंने 19वें ओवर में 10 रन दिए होते, तो मैच का परिणाम अलग हो सकता था। अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे ने शानदार यॉर्कर फेंककर केवल 4 रन देकर एक विकेट लिया। इस ओवर की शानदार गेंदबाजी ने राजस्थान रॉयल्स को अहम 6 रन की जीत दिलाई। इस जीत ने टीम के मनोबल को बढ़ाया और कप्तान रियान बराक के आत्मविश्वास को नई ऊँचाई पर पहुंचाया। इरफान पठान ने कहा कि रियान बराक ने दबाव में भी बेहतरीन निर्णय लिया और यह टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे की भी तारीफ की और कहा कि उनके प्रदर्शन ने मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपने फॉर्म को मजबूत किया है और टीम के खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ अगले मैचों में उतरेंगे। टीम का यह प्रदर्शन कप्तान रियान बराक की नेतृत्व क्षमता और टीम की रणनीति को दर्शाता है। विशेष रूप से, टीम ने मुकाबले के अंतिम ओवर में रणनीति के तहत जोखिम लेने से भी सफलता हासिल की। इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स अपने अगले मैचों में और भी जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी।

अलुआ नूरमान,मैग्नस कार्लसन सेल्फी घटना के बाद सुर्खियों में आए उभरते कजाख शतरंज स्टार

जर्मनी,05अप्रैल 2026। मैग्नस कार्लसन से जुड़े एक वायरल पल ने अचानक दुनिया के उभरते हुए शतरंज के नामों में से एक, अलुआ नूरमान की ओर ध्यान खींचा है। जर्मनी में ग्रेंके फ्रीस्टाइल शतरंज ओपन में मैच से पहले उनकी बातचीत के बाद यह बात सामने आई है।

अलुआ नूरमान कौन हैं?

कज़ाकिस्तान की 18 साल की टैलेंटेड खिलाड़ी नूरमान, कॉम्पिटिटिव शतरंज में कोई अनजान नाम नहीं हैं। वह एक वुमन ग्रैंडमास्टर हैं और ग्लोबल सर्किट की सबसे होनहार युवा खिलाड़ियों में से एक हैं। टॉप जूनियर महिला खिलाड़ियों में शुमार, वह पहले ही एशियन ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप जीतकर और 2024 शतरंज ओलंपियाड में कज़ाकिस्तान के साथ सिल्वर मेडल जीतकर अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी बढ़ती रेप्युटेशन खेल के प्रति उनके निडर अप्रोच और युवा और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार परफॉर्मेंस से आई है। अपने अग्रेसिव लेकिन शांत स्टाइल के लिए जानी जाने वाली नूरमान,उन नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करती हैं जो एलीट टूर्नामेंट में जाने-माने नामों को चुनौती देना चाहते हैं। हालांकि,कार्लसन के साथ उनकी टक्कर के दौरान स्पॉटलाइट काफी बदल गई। अपने गेम से पहले, नूरमान ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सेल्फी ली,यह एक ऐसा पल था जिसमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक का सामना करने की तारीफ़ और उत्साह दोनों झलक रहे थे। कार्लसन ने मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई, जिससे ऐसा लगा कि यह एक अच्छी बातचीत है। लेकिन कुछ ही पलों में, माहौल बदल गया। कार्लसन ने एक आर्बिटर को बुलाया, जिसने यह पक्का किया कि नूरमान का फ़ोन खेलने की जगह से हटा दिया जाए, यह सख्त एंटी-चीटिंग नियमों के अनुसार था, जो मैचों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक लगाते हैं।

आईपीएल इतिहास में पहले 10 ओवर में सबसे कम रन बनाने वाली टीमें

एक ने तो बनाए सिर्फ 31 रन

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले 10 ओवर में सिर्फ 35 रन बना पाई। ये आईपीएल इतिहास में पहले 10 ओवर में बना सबसे छोटा स्कोर है। आईपीएल के इतिहास में अक्सर हमें चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिलती है लेकिन कई बार गेंदबाजों ने ऐसी दहशत पैदा की है कि रन बनाना मुहाल हो गया। जब बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है तो स्कोरबोर्ड पर ऐसे आंकड़े दर्ज होते हैं जिन्हें कोई भी टीम याद नहीं रखना चाहती। आज हम बात करेंगे उन 4 सबसे कम स्कोर्स की जो आईपीएल के शुरुआती 10 ओवरों के खेल के बाद बने हैं।

केकेआर का ऐतिहासिक पतन (31/3)

इस लिस्ट में सबसे ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम है। साल 2009 में जब आईपीएल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में खेला जा रहा था तब डेक्कन चार्जर्स के गेंदबाजों ने कहर बरपाया था। केकेआर के बल्लेबाज वहां की उछाल भरी पिचों पर पूरी तरह बेबस नजर आए और शुरुआती 10 ओवरों में केवल 31 रन ही बना सके जबकि उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यह रिकॉर्ड आज 17 साल बाद भी अटूट बना हुआ है।

राजस्थान रॉयल्स की शर्मनाक शुरुआत (32/5)

उसी 2009 के सीजन में केप टाउन के ही मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलते हुए रॉयल्स की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि 10 ओवर खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 32 रन पर 5 विकेट हो गया था। आधी टीम डगआउट में बैठी थी और मैदान पर मौजूद बल्लेबाजों के पास गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों का कोई जवाब नहीं था।

वानखेड़े में मुंबई इंडियंस का सरेंडर (32/4)

साल 2015 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अपने घरेलू मैदान पर खेलने वाली मजबूत मुंबई इंडियंस किंग्स इलेवन पंजाब के सामने घुटने टेकती नजर आई। शुरुआती झटकों ने मुंबई को ऐसा संभलने का मौका नहीं दिया कि 10 ओवर बीत जाने के बाद भी स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 32 रन ही जुड़ पाए थे और टीम ने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। यह मुंबई के इतिहास के सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक माना जाता है।

हैदराबाद में शमी का जलवा (35/4)

अब बात करते हैं साल 2026 की जहां हैदराबाद के मैदान पर मोहम्मद शमी ने अपनी जादुई गेंदबाजी से नया इतिहास लिख दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए शमी ने अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दिया। शमी की धारदार गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शुरुआती 10 ओवरों में सिर्फ 35 रन बना पाई और 4 विकेट खो दिए। शमी के इस कमबैक स्पेल ने आईपीएल के इस अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में हैदराबाद का नाम चौथे स्थान पर दर्ज करा दिया।

साउथेम्प्टन ने आर्सेनल को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित एफए कप का रोमांच चरम पर है। टूर्नामेंट में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़े उलटफेर का शिकार आर्सेनल हुए है। आर्सेनल जैसी दिग्गज टीम को साउथेम्प्टन ने हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेंट मैरी स्टेडियम में खेले गए एफए कप क्वार्टर फाइनल में साउथेम्प्टन ने आर्सेनल को 2-1 से हराया। मैच की शुरुआत में साउथेम्प्टन ने आक्रामक खेल दिखाया और हाफ टाइम से पहले रॉस स्टीवर्ट ने पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद लियो सेनेजा ने भी बेहतरीन मौके बनाए, लेकिन उन्हें गोल में तब्दील करने में देर कर दी। दूसरे हाफ में साउथेम्प्टन का दबदबा जारी रहा, हालांकि आर्सेनल ने वापसी करते हुए सब्स्टीट्यूट विक्टर ग्योकेरेस के गोल से बराबरी हासिल कर ली।

जब मैच ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था,तभी सब्स्टीट्यूट शिया चार्ल्स ने मैच खत्म होने से पांच मिनट पहले शानदार गोल कर साउथेम्प्टन को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दूसरी ओर, मैनचेस्टर सिटी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लिवरपूल को 4-0 से हराकर लगातार आठवीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस मैच के हीरो रहे एर्लिंग हालैंड, जिन्होंने शानदार हैट्रिक लगाई। उनके साथ एंटोनी सेमेन्यो ने भी गोल कर टीम की जीत को और मजबूत किया। इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप में घरेलू मैदान पर लगातार 18वीं जीत दर्ज की और पुराने रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। कोच पेप गार्डियोला के नेतृत्व में टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और अब तक कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी है। वहीं, चेल्सी ने भी शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की की। स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले गए मुकाबले में उन्होंने पोर्ट वेले को 7-0 से हराया और क्लीन शीट भी बनाए रखी। कुल मिलाकर,इस बार का एफए कप का सेमीफाइनल बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां बड़े क्लब्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

राजस्थान रॉयल्स के बिश्नोई ने कमजोरियों को ताकत में बदला

गुजरात को हराकर जीत दिलाई

अहमदाबाद,05 अप्रैल 2026। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैच में शानदार प्रदर्शन कर टीम को छह विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ बिश्नोई ने अपनी पिछली कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का उदाहरण पेश किया। पिछले आईपीएल सीजन में बिश्नोई का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उन्होंने 11 मैचों में केवल 9 विकेट लिए थे, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था। 25 साल के इस युवा खिलाड़ी ने अपनी लेंथ सुधारने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में कड़ी मेहनत की और अब इसका फायदा उन्हें गुजरात के खिलाफ मैच में मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतते हुए बिश्नोई ने कहा, पिछला सीजन मेरे लिए मुश्किल था। मेरी एक कमजोरी थी–अगर मेरी लेंथ सही नहीं होती थी, तो बैट्समैन मेरे ऊपर आसानी से चौके और छक्के लगा देते थे। मैंने पूरे डोमेस्टिक सीजन में अपनी लेंथ पर काम किया और उसे परफेक्ट किया। मैच में बिश्नोई ने अपनी रणनीति का असर दिखाते हुए साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, और वाशिंगटन सुंदर को विकेट लेकर विरोधी टीम को परेशान किया। सबसे अहम विकेट राहुल तेवतिया का था, जिसे उन्होंने मैच के निर्णायक पल में आउट किया। बिश्नोई ने कहा, राहुल एक फिनिशर हैं। उनका विकेट उस समय लेना बेहद अहम था,नहीं तो गेम किसी भी दिशा में जा सकता था। राजस्थान के लिए यह जीत नर्वस रही, क्योंकि गुजरात ने 211 रन का पीछा करते हुए आखिरी दो ओवरों में 15 रन बनाने थे और उनके पास तीन विकेट बाकी थे। जोफ्रा आर्चर ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ चार रन दिए, जबकि तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर में भी चार रन देकर विपक्षी टीम को रोक दिया। इस नर्वस जीत के बाद राजस्थान को दो मैचों में चार पॉइंट्स मिल गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के भी चार पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण राजस्थान शीर्ष पर है।

CMYK

कंपनी ने कहा 'स्प्यूरियस', लैब ने कहा 'सही' किस पर भरोसा करें ?

नकली दवा का खेलः कंपनी बोली फर्जी,सरकारी लैब ने कर दिया पास!

- Ursocol घोटाला : Sun Pharma ने बताया नकली,सिस्टम ने बचाया असली!
- नकली दवा,असली खेल : छत्तीसगढ़ के औषधि विभाग में बड़ा खुलासा...
- दवा नकली या सिस्टम सेट? रायगढ़ से लखनऊ तक फैला खेल...
- लैब में पास हुई 'नकली दवा'? बेनीराम साहू की भूमिका पर उठे सवाल...
- भाजपा पूर्व विधायक कनेक्शन और दवा जांच विवाद–सिस्टम पर बड़ा सवाल...
- नकली दवा केस में बड़ा नाम चर्चा में : लैब रिपोर्ट क्यों बनी विवाद?

प्रभाव,प्रभार और पास रिपोर्ट-औषधि विभाग में क्या चल रहा है?

कागज पर सही,कंपनी के अनुसार नकली–कहां टूटा सिस्टम?

रायगढ़ से उठे Ursocol 300 मामले में सुधीर केमिस्ट,हर्ष फार्मा,सप्लाई चेन और विभागीय लैब आमने-सामने,बेनीराम साहू और नीरज साहू की भूमिका जांच के घेरे में...

न्यूज डेस्क

रायपुर/रायगढ़,05 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के औषधि विभाग में सामने आया उर्सोकोल 300 दवा का मामला अब केवल एक जांच का विषय नहीं रहा,बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली,पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, इस मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस दवा को निर्माता कंपनी सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड ने स्प्यूरियस (नकली) बताया,उसी दवा को राज्य की सरकारी लैब ने 'मानक गुणवत्ता' का प्रमाण दे दिया, यह विरोधाभास अब एक संभावित बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें सप्लाई चेन,जांच प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका तीनों ही सवालों के घेरे में हैं। बता दे की छत्तीसगढ़ के औषधि विभाग में बेनीराम साहू का नाम इन दिनों सिर्फ एक अधिकारी के तौर पर नहीं,बल्कि एक प्रभावशाली और चर्चित चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया है,बेनीराम साहू भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे बताए जाते हैं और विभागीय व प्रशासनिक गलियारों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है,यही वजह है कि उन पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्हें नियमों से परे काम करने की खुली छूट मिली हुई है,बेनीराम साहू के पास विभाग में कई महत्वपूर्ण प्रभार हैं, जिनमें से एक सबसे संवेदनशील प्रभार औषधि परीक्षण लैब का भी है,वही लैब जहां दवाइयों की गुणवत्ता तय होती है और जहां से जनता की सेहत का सीधा संबंध जुड़ा होता है, इसी लैब से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, रायगढ़ के बड़े दवा व्यापारी सुधीर केमिस्ट से उर्सोकोल 300 दवा का सैंपल उठाया गया, जांच के दौरान दवा निर्माता कंपनी सन फार्मा ने साफ तौर पर इसे नकली (स्प्यूरियस) बताया और कहा कि यह दवा उनकी नहीं है,लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस दवा को कंपनी ने खुद नकली घोषित किया, वही दवा बेनीराम साहू के नियंत्रण वाली लैब में 'पास' हो गई,अब सबसे बड़ा सवाल यही है जब कंपनी दवा को नकली बता रही है, तो सरकारी लैब ने उसे सही कैसे मान लिया? रायगढ़ का उर्सोकोल 300 मामला अब एक बड़े प्रशासनिक और स्वास्थ्य घोटाले का संकेत दे रहा है, इसमें सप्लाई नेटवर्क संदिग्ध, लैब रिपोर्ट विवादित, अधिकारियों की भूमिका सवालों में अब यह जरूरी हो गया है कि निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए, दोषियों पर कार्रवाई हो।

लैब जांच पर सवाल- दस्तावेजों के अनुसार सैंपल की जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही,कोलकाता से अंतिम रिपोर्ट लंबित बताई गई,फिर भी स्थानीय स्तर पर निष्कर्ष जारी कर दिया गया,इससे जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

बेनीराम साहू और नीरज साहू की भूमिका- इस पूरे मामले में औषधि विभाग के अधिकारी बेनीराम साहू व नीरज साहू की भूमिका चर्चा में है,आरोपों के अनुसार लैब उनके नियंत्रण में कार्य करती है,इतने गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जांच को अपेक्षित गति नहीं दी गई,यह भी कहा जा रहा है कि विभाग में कई गड़बड़ियां लंबे समय से जारी हैं,लेकिन प्रभावी कार्रवाई का अभाव रहा है ।

अन्य राज्यों में भी मिला नकली माल- कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसी बैच की नकली दवा बिहार और अन्य राज्यों में भी जब्त की गई,इससे यह मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है,कानूनी पहलू है यदि दवा नकली साबित होती है,तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 की धारा 17बी लागू होगी,दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई, लाइसेंस निरस्तीकरण,जेल और आर्थिक दंड पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनी द्वारा नकली घोषित करने के बाद भी,संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नियमों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए था, स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए थी लेकिन आरोप है कि मामला सामान्य तरीके से दबा दिया गया,जांच आगे नहीं बढ़ पाई।

मामले की शुरुआत : सुधीर केमिस्ट से सैंपल

अगस्त 2025 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन,रायगढ़ द्वारा सुधीर केमिस्ट (राजीव गांधी नगर, रायगढ़) से उर्सोकोल 300 टैबलेट (बैच नंबर GTF3302A) का सैंपल लिया गया, सुधीर केमिस्ट को क्षेत्र का एक बड़ा दवा व्यापारी माना जाता है,जिसकी सप्लाई छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों तक फैली हुई बताई जाती है।

सप्लाई चेन : रायगढ़ से जबलपुर और लखनऊ तक कड़ी

जांच में सामने आया कि दवा हर्ष फार्मा,जबलपुर से खरीदी गई,हर्ष फार्मा ने जीएसटी बिल प्रस्तुत किया,लेकिन मूल निर्माता कंपनी (सन फार्मा) का बिल उपलब्ध नहीं कराया गया, आगे की जांच में संकेत मिले कि दवा की सप्लाई लखनऊ स्थित ए.ए. फार्मा से जुड़ी हो सकती है,यह दवा कई राज्यों से होकर रायगढ़ तक पहुंची,यह पूरा नेटवर्क एक संगठित सप्लाई चेन की ओर संकेत करता है।

कंपनी का दावा : दवा नकली

सन फार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा विभाग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया,सैंपल कंपनी के मूल उत्पाद से मेल नहीं खाता, पैकेजिंग,लेबलिंग और प्रिंटिंग में अंतर है,दवा स्प्यूरियस (नकली) है,यह उत्पाद कंपनी द्वारा निर्मित नहीं है यानी जिस कंपनी का नाम दवा पर था,उसी ने उसे नकली घोषित कर दिया।

सरकारी लैब का उल्टा निष्कर्ष

इसके विपरीत राज्य की सरकारी लैब (रायपुर) ने उसी सैंपल को 'Standard Quality' बताया यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है।

सिस्टम की विफलता या साजिश?

पूरे घटनाक्रम को देखने पर तीन संभावनाएं सामने आती हैं,प्रशासनिक लापरवाही,तकनीकी त्रुटि, संभावित मिलीभगत या संरक्षण 10 सालों से नकली दवाइयों के मुद्दे पर उठते सवाल और इस तरह के मामलों में कार्रवाई का अभाव तीसरे विकल्प को भी मजबूत करता है।

जनता की सेहत पर खतरा

यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं है यह सीधे जनता की जान से जुड़ा हुआ है, नकली दवा का सेवन,गलत इलाज, गंभीर बीमारियों में खतरा,सवाल जो अब भी बाकी हैं कंपनी और लैब की रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों? सप्लाई चेन में मूल बिल क्यों गायब है? जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

मांग...

CBI / EOW से स्वतंत्र जांच
लैब रिपोर्ट का पुनः परीक्षण
पूरे नेटवर्क की जांच
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई

हाइड्रोपोनिक गांजा बेचते 2 युवक गिरफ्तार,छत्तीसगढ़ में पहली बार सामने आया मामला,बड़े नेट वर्क का अंदेशा

दुर्ग-भिलाई,05 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पहली बार हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवक हाई-टेक तरीके से उगाया गया हाइड्रोपोनिक गांजा बेच रहे थे। दोनों आरोपी भिलाई के ही रहने वाले हैं। जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए हाइड्रोपोनिक गांजा बेच रहे थे। छत्तीसगढ़ में हाइड्रोपोनिक गांजे की यह पहली बरामदगी पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह का नशा बड़े महानगरों और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में देखा जाता है। भिलाई नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि, रुआबांधा क्षेत्र में बीज विकास निगम के पास कुछ लड़के नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ गांजा बेच रहे थे, बल्कि नशा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे चिलम और रोलिंग पेपर भी ग्राहकों को दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विक्रम साहू (29) निवासी तालपुरी और यश विश्वकर्मा (27) निवासी हुडको के रूप में हुई है। जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 2 किलो सामान्य गांजा के अलावा छोटे पैकेट में रखा हाइड्रोपोनिक गांजा मिला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 किलो सामान्य गांजा और 2.3 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस को 40 हजार कैश, एक महंगा मोबाइल फोन, चिलम, लाइटर और सिगरेट के साथ गोगो पेपर (रोलिंग पेपर) भी मिला हैं। पूछताछ में सामने आया कि, आरोपी ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इस अवैध कारोबार से जुड़े थे।

चोर का फोटो रायपुर पुलिस ने किया वायरल,घूम-घूमकर कर रहा उठाईगीरी

रायपुर,05 अप्रैल 2026। पुलिस ने एक ऐसे शातिर उठाईगीर चोर की तस्वीर वायरल किया है जो नोटों से भरे बैग छीनकर भागता रहा है। यह स्वयं एक्टिवा पर सवार होकर वारदात करता। पुलिस ने यह तस्वीर पेट्रोल पंप संचालकों को भेजा है। इस शातिर के टारगेट पंप कर्मी होते हैं जो दिन भर की पंप की आय या तो बैंक में जमा करने जाते होते हैं या फिर मालिक के घर पहुंचाने। यह अब तक ऐसी 10 चोरी उठाईगिरी कर चुका है। जिसमें पंप संचालकों को लाखों रूपए की बड़ी रकम का नुक़सान उठाना पड़ा है। इसने तीन पेट्रोल पंप को निशाना बनाया था। ये वारदातें इसने रायपुर और पड़ोस के जिलों में किया था। पुलिस ने पंप मालिकों को फोटो भेजकर सतर्क किया है।

ओड़ीसा के सोनाबेड़ा में भूकंप, जगदलपुर में कंपन की तीव्रता 4.4 रही

रायपुर,05 अप्रैल 2026। बीती रात जगदलपुर में रात 11.32 बजे भूकम्प के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र ओडिशा का सोनाबेड़ा बताया जा रहा है। इसकी तीव्रता 4.4 आंकी गई। यहां घरों में बिस्तर तक हिलने की खबर है। भूकंप का अहसास होने के बाद घबराए लोग घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चे सोए नहीं। ओडिशा के कोरापुट के निकट आए भूकंप के बारे में पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की बढ़ी मुश्किलें...जीएसटी चोरी करने वाले 1.50 लाख कारोबारी रडार पर,10 अप्रैल के बाद घर पहुंचेगा नोटिस!

रायपुर,05 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में राज्य जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी रोकने के लिए अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विभाग के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख (1.50 लाख) व्यापारी ऐसे हैं, जो जीएसटी के दायरे में आने के बावजूद पंजीयन नहीं करा रहे हैं। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 अप्रैल के बाद ऐसे सभी अपंजीकृत कारोबारियों को सीधे नोटिस थमाया जाएगा।

बिजली कंपनी और बैंकों से मिला गुप्त डेटा

दरअसल,विभाग ने इस बार बहुत ही चालाकी से डेटा जुटाया है। विभाग ने उन इलाकों की सूची निकाली है जहां बिजली की खपत अचानक दोगुनी हो गई है। ऐसी फैक्ट्रियों और कारखानों की अब फिजिकल जांच होगी। बैंकों से भी उन व्यापारियों की जानकारी ली जा रही है जिनका टर्नओवर तो करोड़ों में है,लेकिन वे जीएसटी नहीं भर रहे हैं।

जीएसटी नंबर नहीं दिखाया तो 30 हजार का जुर्माना

विभाग ने केवल पंजीयन ही नहीं, बल्कि जानकारी डिस्प्ले करने पर भी सख्ती बढ़ा दी है। अगर आपने अपनी दुकान या दफ्तर के बाहर जीएसटी नंबर की जानकारी चस्पा नहीं की है,तो आप पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। अफसरों के अनुसार,अभी भी 40 प्रतिशत व्यापारी अपनी जानकारी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं,जिन्हें अब चेतावनी के बाद सीधे दंडित किया जाएगा।

कोयला और ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज्यादा गड़बड़ी

सूत्रों ने बताया कि जीएसटी विभाग के अफसरों की खास नजर कोयला और ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वालों पर है। इन दोनों सेक्टर में बिना बिल के कच्चा काम सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा नॉन-ब्रांडेड सामग्री का कारोबार करने वाले भी विभाग के निशाने पर हैं।

जनता और व्यापारियों पर असर

कमिश्नर स्टेट जीएसटी पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मुताबिक, छोटे कारोबारी जिनका टर्नओवर बड़ा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कदम से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए 10 अप्रैल की डेडलाइन बड़ी चुनौती बन गई है।

बिलासपुर में जनता कंस्ट्रक्शन से 9 जुआरी गिरफ्तार

4 लग्जरी-कार और 84,400 कैश जब्त,पुलिस ने थाने में कान पकड़वाया

बिलासपुर,05 अप्रैल 2026। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन कार्यालय में पुलिस ने जुआ खेलते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। देर रात की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 84,400 रुपए नकद, 13 मोबाइल फोन और चार लग्जरी कार जब्त कीं। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 45.84 लाख रुपए आंकी गई है। सिविल लाइन पुलिस को स्मार्ट रोड पर जनता कंस्ट्रक्शन के कार्यालय के बाहर बीएमडब्ल्यू,थार,ग्लेंजा और क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियों का जमावड़ा देखकर शक हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी,जिसके बाद जुआ का यह फड़ पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों की वीडियोग्राफी भी कराई,ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने उनसे कान पकड़वाकर भविष्य में जुआ न खेलने की शपथ भी दिलवाई। यह कार्रवाई शनिवार देर रात एसीसीयू (एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) द्वारा नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में की गई। सिविल लाइन टीआई सुम्मत साहू ने बताया कि जुआ एक्ट के अंतर्गत जिन 9 जुआड़ियों को जुआ खेलते पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में चंद्रप्रकाश पांडेय (43) स्वर्णिम ऐरा सरकंडा, सागर मंगेशकर (30) गजमोहिनी परिसर मंगला,नितेश चंद्र शर्मा (45) आसमा सिटी,दुर्गेश सारथी (32 वर्ष) साकिन जरहाभाठा मिनी बस्ती,अखिलेश त्रिवेदी (52 वर्ष) नेहरू नगर,सेंट फ्रांसिस स्कूल रोड,अमन धर (28) डबरीपारा,आशीष खूंटे (27) कस्तूरबा नगर,रोशन सोनी (31) उसलापुर ओवरब्रिज के पास, सृजन शर्मा (27) 36 सिटी मॉल के पास शामिल है।

नवा रायपुर में बनेगा एससीआर दफ्तर

रायपुर,05 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ राज्य कैपिटल रीजन (एससीआर) की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में नवा रायपुर के सेक्टर-16 में एससीआर कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा,जिसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही एससीआर क्षेत्र की सड़क़ों के चौड़ीकरण और नई सडक़ों के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। एससीआर के संचालक मंडल की बैठक फरवरी में सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में लिए गए फैसलों को अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान एससीआर दफ्तर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके लिए नवा रायपुर के सेक्टर-16 में जमीन चिन्हित कर ली गई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के एक अफसर ने 'छत्तीसगढ़' से बताया कि एससीआर दफ्तर का निर्माण सीबीडी बिल्डिंग के पास किया जाएगा। परियोजना के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कंसल्टेंट नियुक्त किए जा चुके हैं और उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। एससीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सडक़ अधोसंरचना को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर सहित लगभग 23 नगरीय निकायों और करीब 700 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। पहले चरण में सडक़ों के उन्नयन और चौड़ीकरण की योजना तैयार की जा रही है।

हाईकोर्ट का अहम फैसला...कलेक्टर को सीईओ का प्रभार बदलने का अधिकार नहीं,फिर से बहाली के आदेश

बिलासपुर,05 अप्रैल 2026। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कलेक्टर की शक्तियों पर स्पष्ट सीमा तय करते हुए कहा है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) का प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। अदालत ने इस मामले में कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पार्थ प्रतिम साहू ने की। मामला बिलासपुर के निवासी शुभा दामोदर मिश्रा से जुड़ा है। उन्हें 18 जून 2025 को सचिव,आदिम जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा जनपद पंचायत गौरेला (जिला जीपीएम) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद पर पदस्थ किया गया था। वे जून 2025 से इस पद पर कार्यरत थीं। इसी दौरान 11 मार्च 2026 को कलेक्टर, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने आदेश जारी कर उन्हें सीईओ के प्रभार से हटाते हुए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास,गौरेला के कार्यालय में पदस्थ कर दिया। इस आदेश के

खिलाफ शुभा मिश्रा ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया कि 11 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, शासन द्वारा नियुक्त किसी भी जनपद पंचायत सीईओ को हटाने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य शासन की अनुमति आवश्यक होती है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालत ने शुभा दामोदर मिश्रा को पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गौरेला के पद पर पदस्थ करने के निर्देश दिए हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)